What should we call this love: Thackeray brothers are working hard for the BMC elections to be held this year

Editor

After the crushing defeat in the assembly elections, the Thackeray brothers are trying their best to somehow save their existence in the BMC elections to be held at the end of this year, which is the biggest urban body of the country with an outlay of about Rs. 74,500 crores.

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray say they have come together to stay united. For the first time in 20 years, they have shared a political platform on the issue of Marathi identity and imposition of Hindi language. If anyone had any doubts about why the two parties are suddenly joining hands, it is quite obvious. In fact, both these parties had suffered huge losses in the last Maharashtra assembly elections. Shiv Sena (UBT) had won 20 seats in the election, while Eknath Shinde-led Shiv Sena had won 57 seats. MNS did not get a single seat.

So their workers were getting frustrated and wanted them to merge so that they could revive their fortunes. This is why Raj Thackeray quipped that Chief Minister Devendra Fadnavis has done the work by bringing the two cousins together, which Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and others could not do. Uddhav's intention was clear. At an event held in Mumbai, he declared, 'We have come together to stay together. Together we will gain power in Mumbai Municipal Corporation and Maharashtra.'

Elections to the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and other municipal bodies are due later this year. The BMC has a budget in thousands of crores of rupees. It is the largest urban body in India. The BMC

presented its budget for the financial year 2025-26 on February 4, 2025, with a total outlay of Rs 74,427.41 crore. This is 14 per cent higher than previous budgets, which includes several infrastructure projects. Therefore, the BMC is the next battleground for the two political alliances (Mahayuti and Maha Vikas Aghadi) after last year's assembly elections.

The legislature of the urban body ended in 2022 and since then it is being run by a government-appointed administrator. Shiv Sena, which has been ruling the civic body since 1985 (except for 1992-1996), is facing an existential crisis in these elections. Like the Lok Sabha and state assembly elections, two factions of Shiv Sena led by Eknath Shinde and Uddhav Thackeray are set to clash for the Marathi vote base of Shiv Sena in Mumbai. The BJP, which is strengthening its hold in Mumbai, will want to capture the BMC by joining hands with the Eknath Shinde-led Shiv Sena.

On the other hand, the Congress will have to fight for its survival. It is not a major party in the state. After the humiliating defeat of Uddhav and Raj in the assembly elections, these municipal elections offer some hope of revival for them. The inclusion of Hindi as the third language brought a much-needed common issue for Uddhav and Raj Thackeray. The real challenge for the MNS and Shiv Sena (UBT) is that more than 45 per cent of the voters in Mumbai are non-Marathi speakers. They are wary of Shiv Sena's

> **"Raj Thackeray left Shiv Sena in 2005 due to bitter differences with his cousin, after which he formed the MNS. He was projecting MNS as a true champion of the interests of the sons of the soil. But he could not strike a chord with those who did not support his aggressive style, i.e. the Marathi-speaking people of Maharashtra. They preferred Uddhav, who was seen as a moderate leader. Since then, the Shiv Sena and MNS have fought elections against each other, though some of their well-wishers also appealed for a handshake. So, when the Fadnavis government dilly-dallyed on the three-language policy, they saw a big opportunity.**

hardline politics and violence against them. They prefer the BJP, as the Congress is on the decline. Moreover, the Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra are also Hindi-speaking areas. There is no negative sentiment towards Hindi in these regions, as Marathi speakers live in harmony with others. So, if these two parties take their agitation against non-Marathi speakers too far, they may lose.

We can already see that the UBT Sena wants to remain silent. It cannot support the violence perpetrated by MNS workers against non-Marathi speakers. It is also true that the united Marathi platform by the Thackeray brothers may become a problem for Eknath Shinde. But if the non-Marathi voters get scared, it is not a winning formula for the UBT Sena and the MNS. A day before Thackeray's rally, Eknath Shinde's 'Jai Gujarat' slogan in front of Union Home Minister Amit Shah in Pune was seen as an expression of his concern about the new situation. This is why the Shiv Sena (UBT) has drawn a clear line between its stand on Hindi and the more hardline opposition seen in Tamil Nadu.

The Shiv Sena (UBT) is distancing itself from Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin's strong comments after the Thackeray cousins' 'Vijay Rally' in Mumbai. In last year's assembly election, the BJP won 132 seats in the 288-member assembly. It remains the most influential political party in Maharashtra. Its vote share is 26.77 per cent, double the vote share of the second-placed Congress, which has a vote share of 12.42 per cent. Still, even a slight mindset shift in voters in cities like Mumbai, Thane, Pune and Nashik can seriously impact the party. So it is a no-win situation for any party.

छत्तीसगढ़ का परंपरागत तिहार हरेली

राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला

• **छगन लाल लोन्हारे,** उप संचालक जनसंपर्क

प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में हैं। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की इन डेढ़ साल के अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर रिकॉर्ड कायम किया है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत् रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्यौहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदीकर न सिर्फ किसानों को मान बढ़ाया, बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही किसानों के खाते में रमन सरकार के पिछले दो वर्ष का बकाया धान के बोनस 3716.38 करोड़ रूपए अंतरित कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत गांवों में बसता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का व्यापार, उद्योग बढ़ेगा।

परंपरा के अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों की जिद पर अभिभावक जैसे-तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। हरेली तिहार के दिन सुबह से तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं और खेती-किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदाली, फावड़ा, गैंती को साफ कर घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि

औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने-अपने घरों में अराध्य देवी-देवताओं की साथ पूजा करते हैं। गांवों के ठाकुरदेव की पूजा की जाती है।

हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियुक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं। गांव के सहाड़ादेव अथवा ठाकुरदेव के पास यादव समाज के लोग जंगल से लाई गई जड़ी-बूटी उबाल कर किसानों को देते हैं। इसके बदले किसानों द्वारा चावल, दाल आदि उपहार में यादवों को भेंट करने की परंपरा रही हैं।

सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओड़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा-भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती-किसानी का कार्य लगभग हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर, धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण किया जाता है।

हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते है। गेड़ी बांस से बनाई जाती है। दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाड़कर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। उसे नारियल रस्सी से बांधकर दो पउआ बनाया जाता है। यह पउआ असल में पैर दान होता है जिसे लंबाई में पहले कांटे गए दो बांसों में लगाई गई कील के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती हैं, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है। इसलिए किसान भाई इस दिन पशुधन आदि को नहला-धुला कर पूजा करते हैं। गेहूं आटे को गूंथ कर गोल-गोल बनाकर अरंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेटकर गोधन को औषधि खिलाते हैं। ताकि गोधन को रोगों से बचाया जा सके। गांव में पौनी-पसारी जैसे राऊत व बैगा हर घर के दरवाजे पर नीम की डाली खोंचते हैं। गांव में लोहार अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए चौखट में कील लगाते हैं। यह परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। पिहले के दशक में गांव में बारिश के समय कीचड़ आदि हो जाता था उस समय गेड़ी से गली का भ्रमण करने का अपना अलग ही आनंद होता है। गांव-गांव में गली कांक्रीटीकरण से अब कीचड़ की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। हरेली के दिन गृहणियां अपने चूल्हे-चौके में कई प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है। किसान अपने खेती-किसानी के उपयोग में आने वाले औजार नांगर, कोपर, दतारी, टंगिया, बसुला, कुदारी, सब्बल, गैती आदि की पूजा कर छत्तीसगढ़ी व्यंजन गुलगुल भजिया व गुड़हा चीला का भोग लगाते हैं। इसके अलावा गेड़ी की पूजा भी की जाती है। शाम को युवा वर्ग, बच्चे गांव के गली में नारियल फेंक और गांव के मैदान में कबड्डी आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। बहु-बेटियां नए वस्त्र धारण कर सावन झूला, बिल्लस, खो-खो, फुगड़ी आदि खेल का आनंद लेती हैं।

Government is committed to provide nutrition, safe and bright future to the children : Chief Minister Sai

*For the proper development of children, the Department of Women and Child Development and Health should work in coordination
*In the next Collector's Conference, there will be an in-depth review of the schemes run for women and children
*There should be 100% quality implementation of schemes related to children
*The Collector should regularly review the schemes of the Women and Child Development Department at the district level

Raipur: The Chief Minister Vishnu Deo Sai has said that the state government is fully committed to providing nutrition to the children and to provide them a safe and bright future. For the proper development of children, the Department of Women and Child Development and the Health Department will have to work together in mutual coordination.

Chief Minister Vishnu Deo Sai and Women and Child Development Minister Laxmi Rajwade-Photo Credit -CG/PR

Chief Minister Sai on Wednesday July 23, 2025 conducted a high-level review of the progress and implementation of the schemes of the Women and Child Development Department at the Ministry Mahanadi Bhawan and gave important instructions to the officials. He said that regular district-wise monitoring of schemes focused on women and children should be carried out at the Secretary level and it will be thoroughly reviewed in the upcoming Collector's Conference.

In the meeting, Chief Minister Vishnu Deo Sai inquired about the infrastructure, budget and running schemes of the Women and Child Development Department. He said that the department plays a very important role from the point of view of nutrition and security of children, adolescents and women.

He also said that the more sensitively and efficiently the care and nutrition of young children is to be taken care of , so their physical and mental development will be more effectual and strong .

Chief Minister Vishnu Deo Sai , Women and Child Development Minister Laxmi Rajwade, Chief Secretary Amitabh Jain, Principal Secretary to Chief Minister Subodh Kumar Singh, Secretary to Chief Minister P. Dayanand, Rahul Bhagat, Secretary of Women and Child Development Department Shammi Abidi, Director P.S. Elma attending a review meeting -Photo Credit-CG/PR

Chief Minister Sai said that children are the foundation of our country's future and everyone's participation is necessary to strengthen this foundation. He instructed the departmental staff to work actively and with self-motivation at the ground level. He emphasised on ensuring that every child of the state gets proper benefits of supplementary nutrition and departmental schemes.

CM Sai discussed in detailed points including nutrition diet, hot food, its quantity, quality and calories that is to be distributed in Anganwadi centers and stress on the need for continuous monitoring of the distribution process.

Chief Minister Sai took information about the functions of 197 Anganwadi centers operated under PM Janman Yojana and instructed to work with sensitivity and commitment for the all-round development of children of Special Backward Tribe (PVTG) community.

Chief Minister Sai reviewed important indices related to children's nutrition and spoke about making concrete efforts to bring the desired improvement. He said that it is possible to assess the real situation through indices, and wherever deficiencies are seen, quick corrective steps should be taken. The Chief Minister expressed happiness over the better performance in the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana and directed that this progress should continue in this way. He said that small things and behavior have a deep impact on the mental development of children, so Anganwadi workers should make emotional attachment with children with sensitivity.

Chief Minister Sai asked to ensure regular training of departmental staff, so that they can do result-oriented work with technically proficient and research-oriented approach.

Child Marriage Free Chhattisgarh Campaign, Chief Minister Kanya Vivah Yojana, Sakhi One Stop Center, Shakti Sadan, Women and Child Helpline, Mahila Kosh, Beti Bachao Beti Padhao, Mission Vatsalya and other schemes were also reviewed in the meeting.

On this occasion, Women and Child Development Minister Laxmi Rajwade, Chief Secretary Amitabh Jain, Principal Secretary to Chief Minister Subodh Kumar Singh, Secretary to Chief Minister P. Dayanand, Rahul Bhagat, Secretary of Women and Child Development Department Shammi Abidi, Director P.S. Elma and officers and employees of the department were present.

Bhelpuri politics: Who's Asli 'Marathi Manoos'?

> When in doubt, turn to Dostoevsky: "Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up." Try telling that to our ghamandi netas, drunk on real or imagined power (often, also on something equally potent that comes out of a bottle).

Shobhaa De | Irreverent, provocative, opinionated... Shobhaa De has been challenging status quo for four decades... and is at her best when she punctures inflated egoes.

Auothor- Shobha De is one of the most prestigious women novelists of India. She tried her best to create most daring women in all her novels. She has formed very bold and assertive women who challenge the norms of age- old patriarchal society. She has depicted aristocratic urban women in her novels who paved the path for all Indian women.

When in doubt, turn to Dostoevsky: "Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up." Try telling that to our ghamandi netas, drunk on real or imagined power (often, also on something equally potent that comes out of a bottle). At the moment, Mumbai is caught up in a messy language issue, generated by the "Warring Cousins", as the Thackerays – Uddhav and Raj — are benignly referred to, like they are characters out of Enid Blyton's innocuous story books. If only! The protagonists in this tale are middle-aged men (one, with a middle-aged spread to match his age, the other, lean and gaunt to match his temperament). What has Dostoevsky and his blistering tome, The

Brothers Karamazov, have to do with Aamchi Mumbai and its bhelpuri politics? Quite a lot.

Dostoevsky's last and most powerful book tackled everything — from patricide to betrayal, alliances to rifts. Originally published in 1880, the book raised deep, philosophical questions about ambition, greed, blood ties, jealousy. It's worth a re-read, as we in Mumbai wade into swirling monsoon waters, wondering who will drown, get swept away, jump on a raft, or swim to the shore. Dealing with this uncertainty and suspense, hapless Mumbaikars ask themselves: "Why us?"

Why us, indeed!

And who exactly are "us"? Who is the mythical, mysterious "Marathi Manoos", exclusively speaking chaste Marathi in the state of Maharashtra? I am asking myself: what kind of a "Marathi manoos" I am. Here's a primer. Quick! Respond to these questions: "What is the opposite of Marathi?" Answer: "non-Marathi". Question: "What is the opposite of "manoos"? Answer: "Pashu" (animal), "Jantu" (insect), "Bhoot" (ghost), "Rakshas" (demon). I swear I am not making this up. I went straight to the single most trusted, reliable information source: AI. Don't laugh! And this is what AI threw up. The feminine gender for "manoos" does not exist in an exact translation. One has to settle for "Bai" (wife), or "Mulgi" (girl). I don't identify as an animal, ghost or girl. Marathi is my mother tongue.– no debate there.

Which category do I fit into? None, right? If women are entirely excluded from the present, politically-generated debate, should we even care? Or–vote? Most political rallies are testosterone-driven, with a sea of unattractive, shabbily dressed men arriving by the truckload to cheer on cue when their netas address them from an elaborate stage, which is dressed up for a film awards night. This happens across

India. The token presence of women is mainly decorative to project a "happy family" vibe. It was noted that while Rashmi Thackeray was right up there next to her husband Uddhav, Raj Thackeray's wife Sharmila was conspicuously missing at the "victory rally".

A few days after the high-profile rally, a half-dressed, drunk man was videotaped hurling filthy abuses at a woman whose car he had crashed into and damaged. When the clip went viral, shocked netizens raised serious issues about the shirtless, reckless, inebriated goon, who repeatedly warned his victim to back off, yelling standard MC-BC gaalis (in Hindi). Undeterred, the 39-year-old business woman stood her ground, retaliated angrily (in Marathi) and filmed the semi-naked "Marathi manoos", who kept making it worse for herself with the predictable: "Do you know who my father is?" Well... now we do! Rahil Shaikh, the bare-chested driver, is the brat son of Javed Shaikh, an MNS functionary from Thane. He arrogantly told the distraught lady to go and claim her compensation from Raj Thackeray's home. This, in the presence of police officers, who seemed reluctant to take any action against the Tarzan behind the wheel. "Marathi Manoos" could not have found a better poster boy for their brand of violent, disruptive politics. This is NOT Marathi machismo. This is plain criminal conduct. If only Dostoevsky was around to chronicle our ugly mess! After the classic The Brothers Karamazov, he could have tackled "The Cousins Thackeray". I would have happily found him a Marathi translator. "Rikamtekda" is a scrumptious Marathi word. My father would scornfully refer to roadside loafers as "rikamtekde" (plural form) — idlers with nothing to do — or lose — in life. Wastrels. Bums. Low life. Every neighborhood has a few. The Punjabi word for such types is "vella" (feminine: velli). Mumbai is littered with rikamtekdas belonging to different political parties. They look alike (bearded, overweight, sporting prominent orange tikas). Their sole purpose is to terrorize the weak and defenseless, demand haftas and protection money from shopkeepers, wave flags and threaten to teach the public a lesson! Shiv Sena's Buldhana MLA Sanjay Gaikwad assaulted a canteen worker at the Akashwani MLAs' hostel canteen for serving a "rotten daal" that the victim had not cooked in the first place! Definitely something black in those lenses! Gaikwad thundered: "Balasaheb Thackeray has taught us how to deal with such people. And I have used those ways." Shabaash... Gaikwad! He accused police officers of "haraamipan" (rogue conduct), while displaying the same himself.

> **"The low number of women present was a good thing, given the kind of coarse, crude and uncouth jokes being brazenly traded in the speeches. That's no surprise, given the history of these parties. Just asking: Do other states of India have similar categories? Like, say, "Bihari Banda? Non-Bihari?" We've heard of Punjabi Munda, of course. But not a "non-Punjabi". The "non" is crucial when it comes to excluding "outsiders". I go to Bengaluru frequently. But even in that narrow-minded state, nobody has asked me: "Are you a non-Kannadiga?" Maybe I am spared in Karnataka because I am not Kamal Haasan.Like nobody wonders "Are you non-Assamese?" when I visit Guwahati. Nor does anyone stop me in Calicut to accuse me of being "non-Malayalee", or insist that I respond in Malayalam.**

IMPACT FACT - 8.1 | ISSN : 2582-919X

India's Struggle Continues With Gender Equality: A Long Way To Go

Dr. Shruti Jha Bahukhandi | The writer is Deputy Director (Chhattisgarh Project – RUSA), Raipur , Chhattisgarh

Abstract-

While some countries inch forward, others remain stagnant or regress. India, unfortunately, falls into the latter group. Ranked 131 out of 148 countries, India's gender parity score is just 64.1 per cent, making it one of the lowest globally

Introduction -

The World Economic Forum's 2025 Global Gender Gap Report has yet again revealed a bitter truth, both uncomfortable and inconvenient: at the current pace, it will take 123 years to close the global gender gap. That's more than a lifetime for most.

While some countries inch forward, others remain stagnant or regress. India, unfortunately, falls into the latter group. Ranked 131 out of 148 countries, India's gender parity score is just 64.1 per cent, making it one of the lowest globally.

Meanwhile, nations like Iceland, Finland, and Norway continue to hold their positions at the top. Iceland, remarkably, has stayed number one for the fifteenth straight year. It has nearly closed the gender gap in political empowerment, an area where India lags far behind, with just 22.9 per cent parity. Only 13.8 per cent of parliamentary seats here are held by women. That number isn't just low — it is falling.

The problem isn't a single policy failure or a cultural flaw. Studies reveal a layered crisis: intertwining social norms, economic exclusions, weak policy commitments, and systemic political indifference.

So, what is going wrong for India? The problem isn't a single policy failure or a cultural flaw. Studies reveal a layered crisis: intertwining social norms, economic exclusions, weak policy commitments, and systemic political indifference. On paper, India has made strides in some areas. Education, for example, is one such area, with female literacy improving and a gender parity score in education close to 97 per cent. Health indicators, too, have shown some improvement.

However, these achievements are only surface-level gains. Dig a little deeper, and a different picture emerges.

Employment is a case in point. Only 45.9 per cent of working-age women are engaged in the labour force. Many of them are stuck in unpaid or informal roles, earning, on average, nearly 30 per cent less than men. Highly educated women are often pushed out of the workforce by a lack of childcare, unsafe commutes, and rigid gender roles. Urban women, despite formal employment, shoulder

IMPACT FACT - 8.1 | ISSN : 2582-919X

the “second shift” of household labour, while rural women, mainly from marginalised castes, toil in invisible, unrecognised, and often unpaid labour.

Without legal compulsion, political parties continue to field women only where they are unlikely to win. Thus, the cycle continues.

One might ask: don’t we have laws and schemes in place to fix this? We do. However, many have turned out to be more symbolic than structural. Campaigns like “Beti Bachao Beti Padhao” made a splash, but audits later revealed that more than half the money was spent on advertising rather than actual interventions. Schemes to support female entrepreneurs or get girls into science and tech exist, but they are fragmented, poorly funded, and seldom evaluated for real impact.

Gender budgeting, a promising policy tool introduced in India in the early 2000s, has lost its teeth, reduced to a tick-box exercise rather than a genuine attempt to rewire resource allocation

The deeper issue, of course, lies in the cultural realm that still governs everyday life in much of the country. Patriarchal attitudes, often invisible, always persistent, shape how girls are raised, how women are treated, and what they are expected to become. Amartya Sen once spoke of the “missing women” — a phrase that captured how cultural bias, neglect, and violence had literally reduced the number of girls in certain populations. That mindset has not disappeared. Girls are still nudged toward marriage over career, and women who assert themselves in public life are often met with discomfort or disdain.

> **“ From a political standpoint, the picture is no different. Yes, India has had a few strong women in leadership, but these are exceptions, not the norm. One needs to make a distinction here between “descriptive representation” (the presence of women in political office) and “substantive representation” (women actually influencing policy). India has little of either. Even the Women’s Reservation Bill, which was passed in 2023 after decades of delay, is yet to be implemented.**

Compare this with what’s happening elsewhere. In the Nordic countries, gender equality is not an afterthought. It’s foundational. It’s built into their policies, economies, and everyday routines.

Norway, for instance, mandates that 40 percent of seats on corporate boards be reserved for women. Sweden offers nearly 500 days of paid parental leave, shared between both parents. In Iceland, over 70 percent of fathers take paternity leave. These aren’t just perks; they’re deliberate strategies to reshape norms and make care work visible, valuable, and shared. In fact, this approach is rooted in what feminist scholars call the “capabilities approach”, which focuses not just on what rights people formally have but on what they are actually able to do and be. In India, too many women still lack real capabilities, even if they have nominal rights.

So, where does India go from here? We’re not short of resources. We’re not lacking in examples to learn from. What we’re missing is urgency and a recognition that gender inequality is not a “women’s issue”, but a national development crisis. It affects GDP growth, health outcomes, educational achievement, and democratic participation. Yet, it’s often relegated to the margins of policy discourse. Unless there is a serious, sustained commitment from the state, civil society, and political leadership, the promises will remain just that.

Being ranked 131st is not just an embarrassment on paper. It’s a reflection of how far we still have to go, and how much we’ve already chosen to overlook.

Why India Urgently Needs Some Governance Reforms

Manish Tweari | Manish Tewari is a prominent Indian lawyer and politician, currently serving as a Member of Parliament (MP) in the 18th Lok Sabha, representing Chandigarh. He is a member of the Indian National Congress (INC) and a National Spokesperson for the party

The government has set up two administrative commissions, the first on January 5, 1966, under the chairpersonship of former Prime Minister Morarji Desai

A second administrative commission was constituted on August 31, 2005, under the chairpersonship of M. Veerappa Moily. It also had an extensive 13-point mandate-.Manish Tewari

Having had the honour of being elected to the Lok Sabha from three different Parliamentary constituencies with very diverse topographies, demographics and aspirations, the one common thread that runs through all of them is the absolute ramshackle state of our administrative and governance system.

The Ludhiana parliamentary constituency in Punjab, once famously called the Manchester of India, is home to a myriad number of small and medium enterprises embraced by a hard-core rural periphery where agriculture is the principal occupation.

Sri Anandpur Sahib, again in the Punjab, is predominantly a rural constituency with 1,499 villages, 15 odd municipal councils and one municipal corporation. Chandigarh that I am currently representing, is the capital of both the states of Punjab and Haryana, and is a 114-square-kilometre urban agglomeration.

The case of Chandigarh is unique. While the two adjoining districts of Mohali in Punjab and Panchkula in Haryana are run by one deputy commissioner and one senior superintendent of police, Chandigarh has 11 IAS officers and seven IPS officers to boot. This top-heavy bureaucratic structure institutionalises a paralysis of decision making due to the multi layering of babudom.

As an elected representative, it falls to your remit to interact with the administration for both developmental and administrative reasons.

On both counts the experience is far from satisfactory for a variety of reasons.

My experience across all these three geographical expanses leaves me absolutely convinced that if we do not carry out urgent governance and administrative reforms, we will never be able to punch to our

true national potential.
However, before getting into the reasons let us broaden the canvas to encompass the entire nation.
India has a population of 146 crores with a child being born every 2.35 seconds. It hosts 17.7 per cent of the world's population on 2.4 per cent of its area. Of the 146 crore Indians, 95 crores approximately live in rural areas while 51 odd crores stay in urban areas.
For a substantive bulk of these 95-crore people living in the countryside their contact with the Indian state is primarily with a patwari, at best a kanungo, and rarely a tehsildar on the civil or revenue side.
On the law and order or criminal side the bulk of the interface of these people is with either a beat constable, police havildar or at best an assistant sub-inspector in charge of a thana (police station).
Whenever the Indian administration interfaces with the populace, it is not a pleasant occurrence. It is an autocratic, usually extractive and definitely authoritarian experience, to put it mildly. If you happen to live in conflict-prone areas, especially those that are declared as disturbed areas and come within the purview of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), then maybe the only face of the Indian State you would perhaps come across would be one wearing olive green or khaki carrying an AK-47.
The situation is identical in the urban settings, too. The contact of a mass of the people with the government is limited to rent-seeking civic authorities and an exploitive police apparatus. The only saving grace being that people are more easily able to access the instruments of grievance redressal, especially social media, these days.
What is the solution to this problem? One remedy that the political right suggests is mass privatisation of public services. From the late 1970s to the great economic meltdown in 2008, the world witnessed the denationalisation of public services from sewage to railways as the state withdrew from its fundamental role of providing public goods. This phenomenon obtained a fresh push after the collapse of the Soviet instituted command economic model in 1989-90. However, privatisation of public services is a model unsuited to India for the delivery of public services. Where then do we then go from here?
On an average a deputy commissioner/collector (DC) of a district administers a budget of over a 1,000 odd crores for revenue, capital and developmental work. This is a rough and ready back of the envelope estimate as no authentic data seems to exist as to what is the average size of the budget of a district in India. This money flows in both from the Central and state government budgets under different revenue, capital, development and discretionary spending heads.
The DC has a workforce of 1,000 odd people at his disposal The DC's core team consists of two additional deputy collectors, one looking after general administration and the other development. He is further assisted by sub-divisional magistrates, revenue and civic officials down the line.
Not only is the administrative footprint very light on the ground per capita of population, contrary to popular perception, but even the quality of human resource is very poor to put it politely. There is only one way, bottoms-up administrative re-engineering of both the administrative and law enforcement apparatus.
The government has set up two administrative commissions, the first on January 5, 1966, under the chairpersonship of former Prime Minister Morarji Desai. It had an expansive 10-point remit: The machinery of the Government of India and its procedures or work; the machinery for planning at all levels; Centre-state relationships; financial administration; personnel administration; economic adminis-

tration; administration at the state level; district administration; agricultural administration and problems of redress of citizens' grievances.

A second administrative commission was constituted on August 31, 2005, under the chairpersonship of M. Veerappa Moily. It also had an extensive 13-point mandate: Organisational structure of the Government of India; ethics in governance; refurbishing of personnel administration; strengthening of financial management systems; steps to ensure effective administration at the state level; steps to ensure effective district administration; local self-government/panchayati raj institutions; social capital, trust and participative public service delivery; citizen-centric administration; promoting e-governance; issues of federal polity; crisis management and public order. Both commissions submitted voluminous tomes as reports. However, the bureaucracy ably led in this case by the Indian Administrative Service buried both these reports 10 fathoms deep.

Even the political executive has come up short in dismantling colonial era structures of the Mai-Baap Sarkar put in place by the British to oppress Indians.

The one thing that stands out is that no government irrespective of its political colour and character would do any cosmetic administrative reform as well.

It therefore is incumbent on the legislature to step in. The Parliament must constitute a permanent financial committee like the public accounts committee or estimates committee to study, update, recommend and legislate through even the private member bill process a comprehensive across the board administrative reform in the country. Since the Parliament was elected barely a year ago it has a full 48 months to complete the single most important task confronting the nation.

> **Whenever the Indian administration interfaces with the populace, it is not a pleasant occurrence. It is an autocratic, usually extractive and definitely authoritarian experience, to put it mildly. If you happen to live in conflict-prone areas, especially those that are declared as disturbed areas and come within the purview of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), then maybe the only face of the Indian State you would perhaps come across would be one wearing olive green or khaki carrying an AK-47.**
>
> **The situation is identical in the urban settings, too. The contact of a mass of the people with the government is limited to rent-seeking civic authorities and an exploitive police apparatus. The only saving grace being that people are more easily able to access the instruments of grievance redressal, especially social media, these days.**

Manish Tewari is a prominent Indian lawyer and politician, currently serving as a Member of Parliament (MP) in the 18th Lok Sabha, representing Chandigarh. He is a member of the Indian National Congress (INC) and a National Spokesperson for the party

History of China-Pakistan alliance and conspiracies: Plenty of conspiracies against India... Re-evaluation of the Dragon is necessary

To understand the story behind keeping cross-border terrorism out of the joint statement at the recent SCO meeting, one has to look into the history of the Pakistan-China alliance, which is full of conspiracies against India. It is important for India to keep re-evaluating Chinese activities and attitude.

India faced another contradiction in the field of global diplomacy. When terrorism was excluded from the joint statement in the recent meeting of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), India flatly refused to support it. The main reason for this was that the incident of attack on Indian tourists by Pakistan-sponsored terrorists in Pahalgam was not mentioned in it, for which the responsibility was taken by the Pakistani affiliate of Lashkar-e-Taiba.

The SCO was founded in 2001 by China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. India and Pakistan joined it in June 2017, Iran in July 2023 and Belarus in July 2024. Many countries are included in it as observers or dialogue partners, but China wants to maintain its dominance in the Eurasian region. The headquarters of the SCO Secretariat is also in Beijing. A permanent organ of the SCO is the Regional Anti-Terrorism Structure (RATS), which is expected to promote cooperation among member countries against the three evils of 'terrorism, separatism and extremism'.

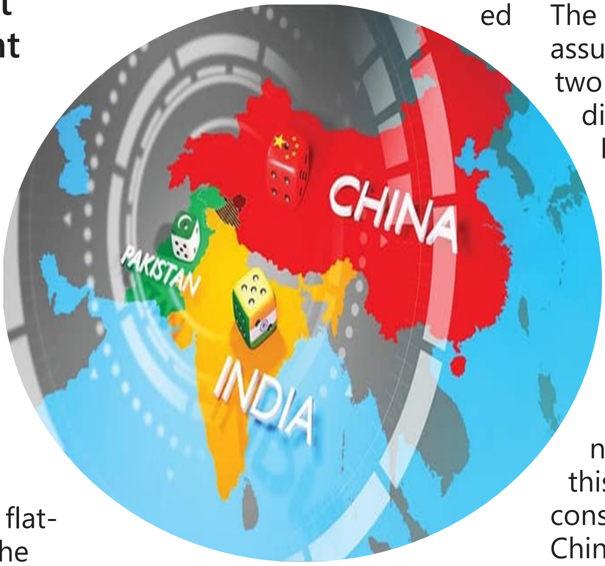

Surprisingly, when China was informed about the Pahalgam terror attack, the Chinese ambassador in Delhi only shed crocodile tears. But Beijing expressed regret over the military action taken by India during Operation Sindoor. Far from punishing Pakistan, China even helped Pakistan escape criticism during discussions at the United Nations.

At the SCO Defence Ministers' meeting, the Indian Defence Minister met his Chinese counterpart and stressed the need to 'bridge the mistrust gap created after the 2020 border standoff by taking action on the ground'. The Indian Defence Ministry assured the country that the two ministers 'agreed to hold discussions at various levels.' But can this resolve the fundamental issues of dispute between the two countries? This puzzle arises when we recall the astonishing advice of a former Indian foreign secretary that 'India should assume that China negotiates to deceive.' And this was from a man who is considered an expert on Chinese affairs and who has served as India's ambassador to China. Did he share his perceptions with his political masters?

A study published in the Strategic Analysis journal of the Institute for Defence Studies and Analyses clearly states that the Chinese declaration of claims to about 50,000 square miles of Indian territory since 1950 was based on unofficial and privately

published maps, known as the Xin Pao maps. Clearly, the Indian governments that have come to power have not been successful in thwarting China's intentions, but have been welcoming to Chinese leaders despite periodic violations. The Pakistan-China nexus has a history. When Pakistan voted to give China a seat in the United Nations, China withdrew the maps disputed by Pakistan in January, 1962 and agreed to engage in border talks in March, 1962. An agreement was signed between the two countries on March 2, 1963. While these actions were taking place, India was suffering from a war waged across the Indian border by Chinese troops.

Under this agreement Pakistan ceded about 5,300 sq km (2,050 sq mi) of territory to China, over which it had no right, as these were Indian territories. In return Pakistan got the area known as Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan is a part of the former princely state of Jammu and Kashmir, which is an 'integral part of India.' Thus a double conspiracy was hatched and executed. The American Times wrote clearly on this matter in 1963 that Pakistan had 'further diminished the hopes of a solution' of the Kashmir problem, because under this Sino-Pakistan Agreement, Pakistan's control over a part of northern Kashmir was recognised by China. The true nature of this expansionist conspiracy came to light when Pakistan was seen approving foreign mountaineering expeditions to the Siachen Glacier, which amounted to drawing a false conclusion from the decisions of the Karachi Agreement signed by the military commanders of India and Pakistan in the presence of United Nations military observers on July 27, 1949.

> "A study published in the Strategic Analysis journal of the Institute for Defence Studies and Analyses clearly states that the Chinese declaration of claims to about 50,000 square miles of Indian territory since 1950 was based on unofficial and privately published maps, known as the Xin Pao maps. Clearly, the Indian governments that have come to power have not been successful in thwarting China's intentions, but have been welcoming to Chinese leaders despite periodic violations. The Pakistan-China nexus has a history. When Pakistan voted to give China a seat in the United Nations, China withdrew the maps disputed by Pakistan in January, 1962 and agreed to engage in border talks in March, 1962. An agreement was signed

According to the letter and spirit of the agreement, NJ 9842 is the northernmost demarcated point on this ceasefire line, from where it was to proceed northwards to the glaciers. Pakistan mistook it as the last point on the Karakoram Pass and considered all the areas in that enclave as its own territory. When this bluff was exposed, the Indira Gandhi government launched a military operation and foiled the Sino-Pakistani conspiracy. But India cannot lower its guard against an expansionist enemy who is eyeing the Indian base at Daulat Beg Oldie, 30 kilometres away in the Depsang Plains. This is a strategic border, which will give them access to the road being built under CPEC and which passes through the territory ceded by Pakistan. This is the main reason why India is not joining the 'One Belt One Road' plan being pursued by China. The Indian government must re-evaluate its conclusions about Chinese activities, stance and attitude and take any decision keeping the bigger picture in mind.

Manipal Academy of Higher Education Hosts 2-day International Conference on Equity, Diversity and Inclusion in Health

The Manipal College of Nursing (MCON), of Manipal Academy of Higher Education (MAHE), Institution of Eminence Deemed to be University, in collaboration with the Faculty of Nursing, University of New Brunswick (UNB), Canada, successfully inaugurated the Manipal International Conference on "Equity, Diversity and Inclusion (EDI) in Health: Envisioning a Future of Global Collaboration for Education, Research & Practice" at the Dr. TMA Pai Auditorium, KMC, Manipal.

Lt Gen (Dr) MD Venkatesh, VSM (Retd) Vice Chancellor of MAHE addressing the crowd at the 2-day International Conference

The conference, which began on July 8, 2025, following a Pre-Conference Workshop on Mixed Methods Research held on July 7, witnessed 230 participants from across India and international destinations. The event is designed to integrate EDI principles into healthcare education, research, and practice through global partnerships and inclusive approaches.

Lt. Gen. (Dr.) M.D. Venkatesh, Vice Chancellor, MAHE, graced the event as the Chief Guest for the inaugural ceremony. In his address, he emphasized the transformative potential of collaborative healthcare approaches and recognized MAHEs commitment to the United Nations Sustainable Development Goals. "Multidisciplinary collaboration holds the power to break barriers within healthcare systems. Dr. T.M.A. Pais visionary contributions in advancing quality education at affordable costs continue to guide our alignment with the United Nations Sustainable Development Goals, particularly in promoting equality and inclusivity. The impactful partnership between MCON and UNB exemplifies this commitment," said Lt Gen (Dr) MD Venkatesh, VSM (Retd) Vice Chancellor of MAHE

Dr. Judith A. Noronha, Dean, MCON and organizing chairperson of the conference, welcomed the gathering and introduced the distinguished guests. Dr. Lorna Butler, Dean, Faculty of Nursing, UNB, Canada, and co-chairperson of the conference, highlighted the critical need for culturally responsive and inclusive health systems across international borders.

A significant highlight of the conference was the Oration Lecture delivered in memory of Late Dr. Aparna Bhaduri by Dr. Anice George, Professor and Head, Research and Collaboration, and Former Dean, MCON, MAHE. The lecture, titled "Promoting Diversity and Inclusion in Healthcare Education, Research, and Practice," was moderated by Dr. Vishnu Renjith, Lecturer and Program Director, School of Nursing & Midwifery, Royal College of Surgeons in Ireland.

"Diversity is not merely an

ideal but an inclusive pathway that ensures all individuals feel welcomed, irrespective of their background, race, gender, or beliefs," stated Dr. Anice George during her oration. "Promoting Diversity, Equity, and Inclusion brings fresh ideas and perspectives, improves patient satisfaction and outcomes, and fosters an equitable and supportive workforce. We need a multi-pronged and proactive approach to embed inclusiveness into organizational culture and policies, making healthcare education, research, and practice equitable, impactful, and future-ready."

The inaugural ceremony featured traditional elements including a floral tribute to Dr. T.M.A. Pai, founder of MAHE, and ceremonial lamp lighting by the dignitaries. Dr. Linu Sara George, Professor and Head, Department of Fundamentals of Nursing, MCON, and convener of the conference, presented an overview of the conference objectives and structure. The two-day conference program includes plenary sessions by national and international speakers, scientific paper presentations, and poster presentations. The conference aligns with the United Nations Sustainable Development Goals, specifically addressing "Good Health and Well-being," "Quality Education," "Gender Equality," "Reduced Inequalities," and "Partnership for Goals."

Dr. Radhika R. Pai, Assistant Professor, Department of Fundamentals of Nursing, MCON, and co-convener of the conference, proposed a vote of thanks during the inaugural ceremony.

> **"Diversity is not merely an ideal but an inclusive pathway that ensures all individuals feel welcomed, irrespective of their background, race, gender, or beliefs," stated Dr. Anice George during her oration. "Promoting Diversity, Equity, and Inclusion brings fresh ideas and perspectives, improves patient satisfaction and outcomes, and fosters an equitable and supportive workforce. We need a multi-pronged and proactive approach to embed inclusiveness into organizational culture and policies, making healthcare education, research, and practice equitable, impactful, and future-ready."**

The conference continued through July 9, 2025, with academic presentations, oration lectures, and deliberations focused on integrating EDI principles into healthcare education, research, and practice.

About Manipal Academy of Higher Education

The Manipal Academy of Higher Education (MAHE) is an Institution of Eminence Deemed-to-be University. MAHE offers over 400 specializations across the Health Sciences (HS), Management, Law, Humanities & Social Sciences (MLHS), and Technology & Science (T&S) streams through its constituent units at campuses in Manipal, Mangalore, Bengaluru, Jamshedpur, and Dubai. With a remarkable track record in academics, state-of-the-art infrastructure, and significant contributions to research, MAHE has earned recognition and acclaim both nationally and internationally. In October 2020, the Ministry of Education, Government of India, awarded MAHE the prestigious Institution of Eminence status. Currently ranked 4th in the National Institutional Ranking Framework (NIRF), MAHE is the preferred choice for students seeking a transformative learning experience and an enriching campus life, as well as for national & multi-national corporates looking for top talent.

India's Strategy Rethink Is Vital in 'Neo Bipolar' World

● Keshav Anand

This drastically new world may never revert to the old one even as Mr Trump weakens domestically or his presidency is over. India is caught between an unreliable America and rival China dominating the second pole. The BJP government needs to rethink its diplomacy and majoritarian domestic politics. It needs a united India as the world gets ready for another major transition, away from the post-Second World War order.

As global power shifts, India must rethink ties with the US and China

The Trump administration's opening six months have exploded many assumptions about America, since the end of the Second World War. These included the United States as the citadel of liberal democracy, free trade and demographic diversity. Since 1991, when the economic liberalisation of India began, better relations with the US have been a cornerstone of Indian foreign policy. In the 21st century, this desire for closer engagement has been demonstrated by both sides.

The epitome of this India-US diplomatic dalliance was Prime Minister Narendra Modi, at the Houston Indian diaspora event on the eve of the 2020 US presidential election, alongside President Donald Trump shouting: "Abki Baar, Trump Sarkar". Despite amounting to blatant interference in the US election, it reflected the shared euphoria. Unbelievably, five years later, with the same person as US President again, there are many doubts and questions facing India's relations with the United States. In particular, India has been concerned about disruption of bilateral trade and, since June, with President Trump's approach towards the four-day India-Pakistan armed conflict and Pakistan itself.

The disruption of global trade, of course, goes well beyond India-US relations. Beginning with the April 2 declaration of universal tariffs as the "Liberation Day", the saga is still

going on. The threatened new tariffs have had shifting deadlines, first July 9 and then August 1, to encourage America's trade partners to swiftly finalise trade deals. Mr Trump's promised 90-deals-in-90-days has been a partial success. After the global markets dropped initially, calm returned, perhaps assuming that Mr Trump's threats are much worse than his actions.

The United States being India's largest trading partner, a similar assumption cannot be India's guide. Even after the fifth round of India-US trade talks on July 14-17 in Washington, an interim trade deal appears to be elusive. India is resisting opening up its agriculture and dairy markets. The US seeks unrestricted access for its industrial goods, automobiles, wines, petrochemicals, agricultural and dairy goods, besides apples, tree nuts, and, controversially, genetically modified crops. On July 7, the US reiterated its threat by writing to 14 nations and setting August 1 as the new deadline

to finalise trade deals. India was not on that list.

Alongside these concerns, President Trump has been repeatedly embarrassing the Indian government claiming that he mediated the India-Pakistan ceasefire by threatening to use the trade weapon. Initially India tried ignoring this, but after rising embarrassment, it publicly denied it, although without criticising Mr Trump.

However, on July 18, speaking to Republican leaders at dinner, while re-chanting old mediation claims, he also said: "I think five jets were shot down". This undermined India's denial and silence on the issue, followed by delayed and vague acceptance by the Chief of Defence Staff. Indian concerns on US-Pakistan relations had already been aroused by President Trump's lunch for Field Marshal Asim Munir, the Pakistan Army chief, on June 16. In fact, insult was added to injury when President Trump invited Prime Minister Narendra Modi, then attending the G-7 summit in Canada, to swing by Washington on his way home. This completely ignored that the optics of the Indian Prime Minister being in the US capital, as the Pakistan Army chief was being hosted to a White House lunch, would be politically toxic in India. This followed the IMF approving a financial package for Pakistan.

Just hours before President Trump's latest claims, US secretary of state Marco Rubio announced that The Resistance Front (TRF), a frontal organisation of the Pakistan-sponsored terrorist group Lashkar-e-Tayyaba, was being designated as a Foreign Terrorist Organisation (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT). The Indian satisfaction was negated by Mr Trump's five-plane barb. A major Indian national daily, next morning, carried a satellite picture of India also having hit Kirana Hills in Pakistan, believed to be a nuclear weapons storage facility. This appeared like a convenient diversionary tactic, on the eve of the Monsoon Session of India's Parliament, during which the Opposition planned to question the government about Operation Sindoor.

"Just hours before President Trump's latest claims, US secretary of state Marco Rubio announced that The Resistance Front (TRF), a frontal organisation of the Pakistan-sponsored terrorist group Lashkar-e-Tayyaba, was being designated as a Foreign Terrorist Organisation (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT).

The diplomatic challenge confronting India is far wider than the two issues described above. A new bipolarity has emerged with the US as one pole and the Russia-China axis as the other. The Cold War bipolarity having ended in 1991, the world first drifted towards America's unipolar dominance, until its military embroilment in Afghanistan and Iraq.

After that a gradual transition had been occurring towards multi-polarity. New plurilateral groups like the G-20, indicated the transition from the G-7 dominated world to one in which emerging powers like China, India and Brazil played a greater role. India had a foot in each camp, despite outstanding and serious differences with China over the land border, as indeed the growing China-Pakistan axis. Another group representing this transition has been Brics, which besides the above three emerging powers also includes Russia and South Africa. The fact that Prime Minister Narendra Modi attended the Brics summit in Brazil indicated a hedging strategy in a world order undermined by President Trump's disruptive announcements and policies. Mr Modi had barely left Brazil when an altercation broke out between the Presidents of the US and Brazil. Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva openly countered Mr Trump's threats by observing that he should desist from pretending to be the world's emperor. President Trump directly targeted Brics, threatening steep tariffs against any member supporting anti-US policies. China rushed to finalise new trade agreements with Brazil, picking up 70 per cent of the Brazilian soyabean crop, shifting from their dependence earlier on American exports. Similarly, the principal members of the European Union are transitioning towards military self-dependence and defence of Ukraine by providing for diminished US military assistance. President Trump, during his first term, had demanded that Nato members increase their defence budgets to two per cent of GDP.

Construction of the world's largest dam started on the Brahmaputra river by China; India is strongly opposing it

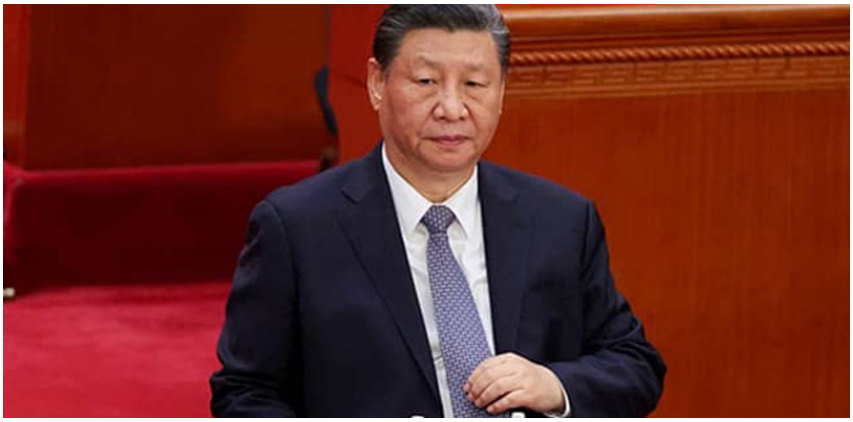

India and Bangladesh are opposing this project of China. Despite this, China has decided to start this project with full vigor. The Chinese Prime Minister Li Qiang himself has announced the start of building the dam on the Brahmaputra River.

Beijing : Despite opposition from India and Bangladesh, China has started construction of the world's largest dam on the Brahmaputra River in southeastern Tibet. It claims that it will produce 300 billion kilowatts of electricity every year. China's state news agency Xinhua said that this dam will meet the electricity needs in Tibet. A total investment of 1.2 trillion yuan (167 billion dollars, about 14 lakh crore rupees) is planned on the project. According to experts, China can use the water of the Brahmaputra River as a weapon against India.

India and Bangladesh are opposing this project of China. Despite this, China has decided to start this project with full force. The start of construction of the dam on the Brahmaputra River has been announced by Chinese Prime Minister Li Qiang himself. On Saturday, a new company named China Yajiang Group was also officially unveiled. Xinhua reported that this company will be responsible for the construction of this hydroelectric project with five waterfall dams located in Nyingchi city in the south-east of Tibet.

China approved the major policy document in 2020

Let us tell you that China has started the $1.5 billion Jam Hydropower Station in 2015 itself. This is the biggest project in Tibet. This dam project on the Brahmaputra is part of China's 14th Five-Year Plan (2021-25). It is part of the major policy document approved by the Communist Party of China (CPC) in 2020. China describes this project as part of the country's economic-social development and long-term objectives to be implemented by 2035.

Dam on Brahmaputra will cause tension between India and China

This river is known as Yarlung Zangbo in Tibet. Dam construction has started on this for the project. It will be built in a huge valley near the Himalayas. From this place the Brahmaputra river turns towards Arunachal Pradesh and then Bangladesh. This dam can cause tension between China and India. China claims that it will not have any adverse effect on the lower areas. Chinese environmentalists have long been concerned about the irreversible impact of dam construction in the Brahmaputra Valley, where the river falls to a height of 2,000 metres (6,560 feet) in an area of 50 kilometres (31 miles). The area is a national nature sanctuary and one of the country's major biodiversity centers.

The dragon can also play a devious trick of releasing huge amounts of water

This project has raised concerns in India, because due to the size and scale of the dam, China will be able to control the water flow of the Brahmaputra. In case of a conflict with the neighboring country after getting rights over the water flow, China can also play a devious trick of releasing huge amounts of water to flood the border areas. According to experts, China can use the water of the Brahmaputra river as a weapon against India. If needed, it can release the water stored in the dam in Tibet without any prior notice. This can cause floods in the lower areas of Arunachal Pradesh and Assam and worsen the situation. Construction of a big dam affects not only residential areas but also forests and wild animals. The flow of the river brings silt which is rich in minerals and is essential for agriculture and stability of coastal areas.

IMPACT FACT - 8.1 | ISSN : 2582-919X

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

शोधकर्ता- नाम-सत्याभारती सूयार्र
एम.एड. (प्रशिक्षार्थी),
प्रगति महाविद्यालय, प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) पता- रानी बगीचा, जशपुर।

शोध निर्देशक- श्री भुनेश्वर यादव
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा संकाय)
प्रगति महाविद्यालय, प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
पता- रानी बगीचा, जशपुर।

1. प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का आधार स्तंभ है। यह न केवल ज्ञान का अर्जन है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया भी है। शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है, उसे नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं व्यावहारिक दृष्टि से परिपक्व बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य व्यक्ति के भीतर छिपी क्षमताओं को विकसित करना, उसमें मानवीय मूल्यों का समावेश करना और उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाना शब्द 'शिक्षा' की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु 'शिक्ष' से हुई है, जिसका अर्थ है - 'सिखाना' या 'ज्ञान देना'। शिक्षा केवल औपचारिक संस्थाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह प्रक्रिया परिवार, समाज, विद्यालय, अनुभव, परंपराओं तथा संस्कृति के माध्यम से निरंतर चलती रहती है। शिक्षा का वास्तविक स्वरूप तभी स्पष्ट होता है जबवह व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पक्षों को संतुलित रूप से विकसित करे।

2. निर्देशन का अर्थ

मनुष्य एक सामाजिक, बृद्धिमान और विवेकषील प्राणी है। इसी के आधार पर वह संसार के अन्य प्राणियों से बिल्कुल भिन्न है। वह बुद्धि के बल पर ही समाज के पर्यावरण और अन्य प्राणियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसे सामना करना पड़ता है जिसके लिए उसे अपने से बड़ो का सहयोग लेना पड़ता है। इस सहयोग के आधार पर वह समस्याओं के सम्बन्ध में उचित निष्कर्ष निकालने में अपने उद्देष्यों को प्राप्त करने में उसे आसानी होती है। निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और कौषलों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और अपने में निहित क्षमताओं का उचित प्रयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जैसे - जब भगवान राम को लंका में सीता की खोज करायी थी तो हनुमान को अपनी शक्ति का आभास नहीं था जब उन्हे उनके श्क्ति और क्षमताओं के बारे में बताया गया तो वे समुद्र को लाँध कर ही पार कर गए। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना नहीं है बल्कि इसके आधार पर व्यक्ति की क्षमताओं का उसे बोध कराकर उसे इस योग्य बनाना होता है। जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम हो जाए। निर्देशन की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है।

3. शिक्षा में निर्देशन

शिक्षा के निर्देशन का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक-सामाजिक ज़रूरतों के अनुरूप मार्गदर्शन देना है ताकि वे सूचित निर्णय लेकर अपनी पूर्ण क्षमता विकसित कर सकें। यह प्रक्रिया न केवल शैक्षणिक-उपलब्धि और करियर-तैयारी में सहायक होती है, बल्कि मानसिक-सामाजिक कल्याण और आत्म-नियमन कौशल भी सुदृढ़ करती है। शैक्षिक निर्देशन - सही विषय-पाठ्यक्रम चयन, अध्ययन-रणनीति, परीक्षा-तैयारी और सीखने की बाधाओं का समाधान। व्यावसायिक निर्देशन - रुचि-योग्यता आकलन, उद्योग-सूचना, इंटर्नशिप/प्रशिक्षण के अवसर और करियर-पथ निर्धारण। व्यक्तिगत-सामाजिक निर्देशन - आत्म-पहचान, भावनात्मक-समायोजन, सहानुभूति, संघर्ष-प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता।

4. अध्ययन की आवश्यकता

नैतिकशिक्षा और शैक्षिकउपलब्धि के अन्तर्सम्बन्ध पर अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि

(1) मूल्य-आधारित अधिगम छात्रों के व्यवहार और कक्षा-अनुशासन को प्रभावित करता है, पर इसकी प्रत्यक्ष भूमिका अकादमिक परिणामों में कितनी है, यह स्पष्ट संख्यात्मक साक्ष्य अभी सीमित है।

(2) लिंग, क्षेत्र (ग्रामीण-शहरी) और सामाजिक-आर्थिक स्तर के आधार पर नैतिककार्यक्रमों के प्रभाव में अंतर दिखाइ देता हैकृइन भिन्नताओं को मापना नीति-निर्माताओं को लक्षित हस्तक्षेप तय करने में मदद करेगा।

(3) भारत में नई शिक्षा नीति 2020 ने "मूल्य-सम्पन्न शिक्षा" को मुख्य धारा में रखा है, इसलिए विद्यालय-स्तर पर इसके प्रभाव-आकलन हेतु ताज़ा डेटा की ज़रूरत है।

(4) दुनिया-भर के शोध दिखाते हैं कि उच्च नैतिक मानदंड वाले वातावरण में विद्यार्थियों की आत्म-नियंत्रण व सीखने की अभिप्रेरणा बढ़ती है, पर भारतीय संदर्भ में दीर्घकालिक अध्ययन दुर्लभ हैं।

5. संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन

पूर्व में किए गए शोध कार्य-

5.1 भारत में किये गए शोध कार्य

- सिंह, रितु (2014) ने जन्मक्रम पर आधारित निर्देशन सम्बन्धी आवश्यकताओं, विषयपर शोधकार्य कर निष्कर्ष निकाला कि जन्मक्रम का निर्देशन सम्बन्धी आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- देशमुख, के (2014) ने शारीरिक व विकलांग बालकों की समाज में निर्देशन आवश्यकताओं की पीएच.डी. स्तरीय शोध कार्य किया। शारीरिक अपाय तथा सामान्य विद्यार्थियों के निर्देशन आवश्यकताओं में सार्थक अन्तर नही पाया गया। उच्च स्वधारणा वाले विद्यार्थियों में दूसरों पर

निर्भर रहने की भावना कम पायी गयी।

▪ पंडित, आई. ए. (2010) ने युवकों की निर्देशन आवश्यकता और समाजोपयोग शिक्षण पर शोधकार्य किया। किशोरों का गूढ़तम सामाजिक, संवेगात्मक व विवेकशैली समायोजन व निर्देशन सभी क्षेत्रों में मिला। समाजोपयोग व निर्देशन के सभी क्षेत्रों में अवकाश प्राप्त विद्यालय स्तर सर्वाधिक अच्छा रहा।

▪ 5.2 विदेश में किये गए शोध कार्य एल. पेरी एवं डी. निकोल्स (2014) "हाई स्कूल विद्यार्थियों की मूल्यों एवं मातापिता की आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा चयन" विषय पर अध्ययन किया। इसमें शारीरिक एवं सामाजिक शिक्षा ग्रहण करने को पारिवारिक वातावरण से जोड़कर देखा गया।

▪ खेमलानी भूषि जुगनू (2013-14) "विज्ञान विद्यार्थियों के अध्ययन आदतों पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव" विषय पर अध्ययन किया गया। निष्कर्षतः अध्ययन आदतों के निर्देशन की उपेक्षा शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है।

▪ कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग (2013) "स्कूल काउंसलिंग इफेक्टिवनेस" विषय पर शोध किया गया। विद्यार्थियों के लिए नियमित परामर्श कार्यक्रम की उपयोगिता बताइ गई जिससे वे मानसिक समस्याओं से उबर सकें।

6. अध्ययन का उद्देश्य

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों उनके पारिवारिक वातावरण का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन करना।

2. उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों उनके पारिवारिक वातावरण का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन करना।

3. उच्चतर माध्यमिक स्तर के अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों उनके पारिवारिक वातावरण का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन करना।

7. अध्ययन की परिकल्पनाएं

इस शोध में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया-

▪ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों पर पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

▪ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों पर पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

▪ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय एवं अषासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों पर पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

8. अध्ययन की क्षेत्र व परिसीमन -

वर्तमान अध्ययन का विषय है - "उत्तर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव"। यह विषय व्यापक है, किन्तु सीमित संसाधनों, समय और साधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस अध्ययन की परिसीमा निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

समय एवं साधनों की सीमितता के कारण शोध अध्ययन की परिसीमाएं निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है-

1. प्रस्तुत अध्ययन में केवल रायपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा।

2. प्रस्तुत अध्ययन में 1 शासकीय एवं 1 अषासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सम्मिलित किया जायेगा। 3. प्रस्तुत अध्ययन में 100 विद्यार्थियों को न्यादर्ष के रुप में सम्मिलित किया जायेगा।

क्रमांक	विद्यार्थी	शास. शाला	अशास. शाला	योग
1	छात्र (बालक)	25	25	50
2	छात्रा (बालिका)	25	25	50
कुल योग		**50**	**50**	**100**

9. शोध विधि

इस शोध में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा ताकि उत्तर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों से उनके पारिवारिक वातावरण और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। सर्वेक्षण के दौरान हम दोनों वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक प्रश्नों का उपयोग करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जबकि व्यक्तिपरक प्रश्नों में खुला सवाल होगा, जिसे विद्यार्थी अपनी सोच और अनुभव के आधार पर उत्तर देंगे। शोध किसी भी शैक्षणिक, सामाजिक या वैज्ञानिक क्षेत्र में तथ्यात्मक एवं प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम है। शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोध समस्या के लिए उपयक्तु शोध विधि का चयन किया गया है या नहीं। शोध विधि का अर्थ है - उस विशेष प्रक्रिया या उपाय का चयन, जिसके माध्यम से शोध कार्य संपन्न किया जाता है। शोध विधि का चयन करते समय शोधकर्ता को अत्यंत सावधानी बरतनी होती है क्योंकि शोध विधि का सीधा प्रभाव शोध के निष्कर्षों की विश्वसनीयता एवं सत्यता पर पड़ता है।

10. जनसंख्या

शैक्षिक शोध में "जनसंख्या" उस समस्त समूह को कहा जाता है, जिससे संबंधित कोई विशेष जानकारी या निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अतः शोध की जनसंख्या उसी वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को बनाया गया है जो अध्ययन की दृष्टि से उपयुक्त एवं प्रतिनिधिक हैं। इस अध्ययन की जनसंख्या का स्वरूप इस प्रकार है- इस शोध में रायपुर जिले के चयनित शासकीय व अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। कुल 100 विद्यार्थी जनसंख्या में रखे गए, जिनमें 50 बालक (लड़के) तथा 50 बालिकाएँ (लड़कियाँ) शामिल हैं। सभी विद्यार्थी कक्षा 11वीं एवं 12वीं के हैं तथा इनकी आयु 15 से 18 वर्ष के मध्य है। ये विद्यार्थी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से चयनित किए गए हैं, ताकि पारिवारिक वातावरण की विविधता को समाविष्ट किया जा सके।विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों से संबंध रखते हैं- जैसे निम्न वगर, मध्य वर्ग एवं उच्च वर्ग। जनसंख्या का चयन क्यों महत्वपूर्ण है? इस प्रकार संतुलित जनसंख्या का चयन इसलिए किया गया ताकि - लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके (बालक बनाम बालिका)।

11. न्यादर्श विधि

शोध प्रक्रिया में न्यादर्श का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। जब किसी संपूर्ण जनसंख्या से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करना संभव न हो, तब उस जनसंख्या के एक सीमित, लेकिन प्रतिनिधिक भाग का चयन किया जाता है, जिसे न्यादर्श कहा जाता है। यह न्यादर्श पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है और इसी के आधार पर निष्कर्षों की सामान्यीकरण की प्रक्रिया की जाती है। इस अध्ययन में न्यादर्श का स्वरूप निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है- इस अध्ययन के लिए कुल 100 विद्यार्थियों का

चयन किया गया। इनमें 50 बालक (लड़के) एवं 50 बालिकाएँ (लड़कियाँ) सम्मिलित की गईं। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक नमूना चयन विधि द्वारा किया गया, जिससे प्रत्येक छात्र को समान अवसर मिला। ये विद्यार्थी रायपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से चनु गए हैं। विद्यार्थियों को अलग-अलग पारिवारिक संरचना (संयुक्त परिवार, एकल परिवार), माता-पिता के शिक्षित या अशिक्षित होने, तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर भी विविधता के साथ चुना गया है। न्यादर्श चयन की प्रक्रिया में ध्यान रखे गए बिंदु- 1. लैंगिक संतुलन - लड़के और लड़कियों की संख्या समान रखी गई, ताकि दोनों वर्गों की

मानसिक स्थिति की तुलना की जा सके। 2. क्षेत्रीय विविधता - शहरी और ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों को समान अवसर दिया गया। सामाजिक पृष्ठभूमि - विद्यार्थियों को निम्न, मध्य व उच्च वर्ग से सम्मिलित किया गया, जिससे पारिवारिक वातावरण में विविधता आए।

क्रमांक	चयनित विद्यालय का नाम	छात्र	छात्रा	कुल
1.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुरा, जिला–रायपुरा, रायपुर (छ.ग.)	25	25	50
2.	शिवोम विद्यापीठ, महादेव घाट रायपुर, जिला–दुर्ग, (छ.ग.)	25	25	50
	कुल योग	50	50	100

12. उपकरण

1. पारिवारिक वातावरण मापक प्रश्नावली - शालू सैनी एवं परमिंदर कौर 2. मानसिक स्वास्थ्य मापक प्रश्नावली - रुची सिंह एवं रागिनी मिश्रा

13. सांख्यिकीय विष्लेषण

मध्यमान $\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$

प्रमाप विचलन $SD = \sqrt{\frac{\sum(X-\bar{X})^2}{N}}$

क्रांतिक अनुपात $C.R. = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_2^2}{N_2}}}$

टी–टेस्ट $t = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{N_1} + \frac{S_2^2}{N_2}}}$

14. परिकल्पना

प्रदत्त का प्रमापीकरण प्रदत्त का संकलन होने के बाद उसका विश्लेषण हेतु प्रदत्त को व्यवस्थित क्रम में रखना होता है।

सारणी 1 शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों पर पारिपारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर (ज-जमेजपरिणाम)

चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t मान	सार्थकता
शासकीय	25	180	15.2	2.34	असमान्य
अशासकीय	25	190	14.7		

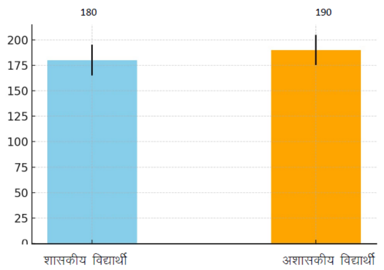

ग्राफ 1 शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों पर पारिपारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर

व्याख्या- इस सारणी से पता चलता है कि अषासकीय विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य स्कोर शासकीय विद्यार्थियों की तुलना में असमान्य है, अतः अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी 2 अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों पर पारिपारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर (t-testपरिणाम)

चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t मान	सार्थकता
अशासकीय	25	185	16-0	1.12	असमान्य
शासकीय	25	187	15-5		

व्याख्या- इस सारणी से पता चलता है कि अषासकीय विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य स्कोर शासकीय विद्यार्थियों की तुलना में असमान्य है, अतः अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी 3 शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों पर पारिपारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर

क्रमांक	चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता
1	शासकीय स्कूल	50	40.7	5.81	2.67	असमान्य
2	अशासकीय स्कूल	50	43.7	5.4		

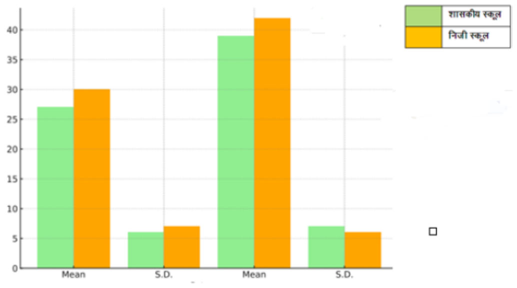

ग्राफ - 3 अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों पर पारिपारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर

व्याख्या - इस सारणी से पता चलता है कि अषासकीय विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य स्कोर शासकीय विद्यार्थियों की तुलना में असमान्य है, अतः अंतर नहीं पाया जायेगा।

15. निष्कर्ष एवं परिणाम

शोध अध्ययन "उत्तर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव" का उद्देश्य यह जानना था कि पारिवारिक वातावरण विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस शोध के अंतर्गत तंपचनत जिले के 100 विद्यार्थियों (50 लड़के और 50 लड़कियाँ) का चयन किया गया और उनके पारिवारिक वातावरण तथा मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया।

16. भावी शोध हेतू सुझाव

1. माता-पिता को जागरूक बनाना आवश्यक- माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझें।

2. सकारात्मक पारिवारिक वातावरण का निर्माण- विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि परिवार में स्नेह, सहयोग और समझदारी का वातावरण हो।

3. विद्यालय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा- विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

4. मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र- प्रत्येक विद्यालय में एक प्रशिक्षित काउंसलर या मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों की समस्याओं को समझे और उन्हें उचित मार्गदर्शन है।

5. अभिभावक-शिक्षक सहयोग- विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में अभिभावक और शिक्षक दोनों की संयुक्त भूमिका होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- शर्मा, रामनाथ एवं शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) - शैक्षिक मनोविज्ञान, एटलांटिक पब्लिकेशन, नई दिल्ली।पृष्ठ संख्यारू 152-187
- चौहान, सुरेश (2012) - बाल मनोविज्ञान, विनायक पब्लिकेशन, आगरा।पषृठ संख्यारू 98-132
- वैग, एल. एस. (2007) - शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंडल, आगरा।पृष्ठ संख्याः 65-100
- बौमरिंड, डायना (1991) - पालन-पोषण शैली और किशोर विकास, जर्नल ऑफ़ अर्ली एडलोसेंस, खंड 11, अंक 1।पृष्ठ संख्याः 56-95
- स्टीनबर्ग, लॉरेंस (2001) - माता-पिता एवं किशोरों के संबंध, जर्नल ऑफ रिसर्च ऑन एडलोसेंस, खंड 11।पृष्ठ संख्याः 1द्19
- कॉंगर, आर. डी. एवं कॉंगर, के. जे. (2002) - मिडवेस्टर्न परिवारों में लचीलापन, जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली, खंड 54, अंक 3। पृष्ठ संख्याः 500-510
- अमाटो, पी. आर. (2000) - तलाक का बच्चों पर प्रभाव, जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली, खंड 62, अंक 4। पृष्ठ संख्याः 1269-1287
- योशिकावा, हीरोकाज़ू (1994) - परिवारिक समर्थन और बाल विकास, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, खंड 49। पृष्ठ संख्याः 274-283
- शर्मा, जयप्रकाश (2011) - बाल विकास एवं शिक्षा, अमन पब्लिकेशन, जयपुर।पृष्ठ संख्याः 121-144 राव,
- शंकर सी. एन. (2009) - सामाजिक मनोविज्ञान, एस. चन्द एंड कम्पनी, नई दिल्ली।पृष्ठ संख्यारू 201-215

महाविद्यालय स्तर कि बालिकाओं की शिक्षा कि समस्याओं के संबधं में तुलनात्मक अध्ययन

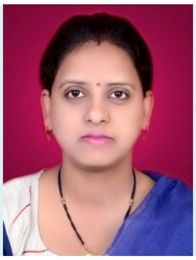

शोधकर्ता- प्रिया कुमारी
एम.एड. (प्रशिक्षार्थी),
प्रगति महाविद्यालय, प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर

शोधनिर्देशक-भुनेश्वर यादव
सहा. प्रध्यापक (शिक्षा संकाय),
प्रगति महाविद्यालय, प्रगति महाविद्यालय,
चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

सारांश

शिक्षित बालिका राष्ट को महानतम बना सकने में सर्वदा सफल होती है। अशिक्षा से सरकारों पर परिमाजर्न नही होता ं आज के सदंर्भ में बालिका शिक्षा अत्यतं अनिवार्य हो गई है। बालिकाएँ मानव को अपनी कोख में धारण कर उसे पुष्पित और पल्लवित कर समाज को अमूल्य मानव, ससांधन, उपलब्ध कराने का माध्यम है। यह कितनी विडम्बना की बाल है कि परिवार ओर समाज की धूरी बालिकाओं की दयनीय स्थिति को समुन्नत बनाने मे ंअभी काफि पीछें है। आज के सदंर्भ में बालिका शिक्षा अत्यतं अनिवार्य हो गई है। दि हम अपनी सस्ंकृतिक धरोहर को सजोए रखना चाहते है और साथ ही देश का बहर्मुखी विकास चाहते है, तो भारत की बेटी को, शिक्षा उपलब्ध करानी ही होगी। अन्यथा एक पक्षीय विकास बहुत लम्बे समय तक राष्ट एंव समाज की प्रगति को वहन नही कर सकता।

बालिकाएँ समाज की आधार स्भंभ होती है। विकास की सीढियों पर जाने के लिए बालिकाओं में परिवर्तन लाना अनिवार्य हैं। शिक्षा के क्षत्रे में बालिकाबों को उतना ही अधिकर है, जितना कि पुरूषों को है सामाजिक सस्ंकृति बालिकाओं की सर्वागिक विकास हेतु शिक्षा के प्रचार – प्रासर अत्यतं आवश्यकों के प्रति समाज सें विचार में परिवर्तन लाना जिसमें कि बालिकाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार सामाजिक परिवर्तन में महिला शिक्षा का महत्वपूर्ण अगं व कार्य है।

प्रस्तावना

इस पुस्तक का लक्ष्य शोध प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाली भौलियों की एक श्रृंखला के माध्यम से भोध और जांच की रहस्यपूर्ण बनाने में मदद करना है। इनमें से प्रत्येक लेखन परियोजनाएनोदटेटेड ग्रंथसूची, प्रस्ताव, साहित्य समीझा और भोध निंबध–एक दूसरे पर आधारित है। भोध एक सतत् और विकसित होने वाली प्रक्रिया है, और इनमें से प्रत्येक परियोजना आपको अगले की ओर बढ़ने में मदद करती हैं।

हमने अपनी एनोटेटेड ग्रथं सूची में, अपने किसी विशय पर अपनी जांच भुारू की, अपनी जांच की चौड़ाई को परिभाशि करने के लिए व्यापक रूप से पढ़ा। हमने अपने द्वारा जांचे गए पहले स्रोतों का सारांश और या मूल्यांकन करके इसे रिकॉर्ड किया। अपने प्रस्ताव में, हमने एक योजना बनाई और आगे बढ़ने के लिए विचार विकासित किए। इससे हमको यह अच्छी समझ मिली कि हम कहां खोज जारी रख सकते है।अपने साहित्य समीक्षा में, हमने अपने विशय के इर्द – गिर्द बड़ी बातचीत की समझ विकसित की और मौजूदा शोध की स्थिति का आकलन किया। इन लेखन परियोजनाओं में से प्रत्येक के दौरान, आपको विशय के बारे में आपका ज्ञान बढ़ता गया ,और आप इसके प्रमुख मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने लगे ।

हमने एक विशय स्थापित कर लिया है और एक दूसरे के साथ बातचीत में स्रतों को इकट्ठा कर लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आवाज से उस बातचीत में योगदान दें। अपने भोध के इतने सारे काम पूरे होने के बाद, अब में अपना ध्यान एक स्पश्ट थीसिस के साथ एक मजबूत शोध निबंध तैयार करने पर लगा सकते है। पहले तीन लेखन परियोजनाओं में आपके द्वारा विकाकसत व्यापक ज्ञान के कारण आप अपने शोध के टूकड़े को एक साथ रखने के बारे में अधिक सोच पाएगे बजाय इसके कि आप लिखते समय ही भोध करने की कोशिश करें।

इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे थोड़ा और शोध करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, हमको, अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए अपने विषय की मूल बातें जानने की कोशिश करने के बजाय, एक या दो मुख्या जानकरी पर रणनीतिक रूप सं ध्यान केद्रित करने की आव यकता हो सकती है।

लेकिन थीसिस या तर्क के बारे में क्या हो सकता है कि हमने प्रक्रिया के आरंभ में ही एक स्पष्ट विचार विकसित कर लिया हो, या हो सकता है कि आप धीरे – धीरे किसी महत्वपूर्ण दावे पर पहूँच गए हो जिसका बचाव करना चाहते हो या कोई आलोचना करना चाहते हो: जैसे आप अपने विशय के बारे में और अधिक पढ़ते हैं। हो सकता है कि आप अभी भी सुनिश्रित न हीं कि आप क्या तर्क देना चाहते हैं। चाहे आप कहीं भी हों, यह अध्याय आपको शोध निबंध की शैली को समझने में मदद करेगा। हम एक अच्छी थीसिस और तर्क की मूल बातें स्रोतों का उपयोग करने के विभिन्न तरीके और अपने निबंध को व्यवस्थित करने की रणनीतियों की जाँच करेंगे।

जबकि यह अध्याय कॉलेज कही कक्षा में आपको द्वारा लिखे जाने वाले शोध निबंध के प्रकार पर ध्यन केद्रित करेगा कौशल व्यापक रूप से लागू होते हैं। शोध अकादमिक, पेशेवर और सार्वजनिक दुनिया में कई अलग– अलग रूप लेता है। पाठयक्रम या अनुशासन के आधार पर शोध का मतलब कक्षा के लिए एक सेमेस्टर–लंबा प्रोजेक्ट या उन्नत डिग्री के लिए कुछ वर्शो का शोध हो सकता है। जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरणें में देखेंगे, शोध में एक संक्षिप्त, दो – पृश्ठ निष्कस या एक सरकारी रिपोर्ट सामिल हो सकती है जो सैकड़ों पृष्ठों में फैली हुई है।जिसमें भारी मात्रा में मूल डेटा है।

सबसे बढ़कर, अच्छी शोध अपने पाठकों के साथ मिलकर मॉजूदा बातचीत के आधार पर नए विचारो की सामने लाता है। एक अच्छा शोघ निबंध प्रांसशिक तथ्यो, विश्लेशण और विचारो के आघार पर विशय के इर्द–गिर्द बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दुसरे के शोध का उपयेाग करता हैं।

2.1 पूर्व में किया गया शोध कार्य –

पर्वू में किए गए भारतीय पृष्ठभूमि में तथा विदेशी पृष्ठभूमि में किए गए शोध अध्ययन निम्नलिखित है। किसी भी विषय में किसी विशेष शोध – प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्त्ता को पूर्व सिद्ध ातों एवं शोधो ंये भली – भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध– प्रारूप की प्रारंभिक अवस्था में इसके सैद्धातिक एवं शोध साहित्य का पनुर्निरीक्षण करना चाहिए।

2.1.1 भारत में किए गए शोध आध्ययन –

01. कुमार आर (1999) – निम्न वर्ग की बालिकाओं मे ंशिक्षा के महत्व का अध्ययन। उपरोक्त अध्ययन पश्चात् यह पाया गया कि निम्न वर्ग की बालिकाओं मे ंशिक्षा कें प्रति व्यापक जागरूकता पाई गई, अपितु शासन भी विभिन्न योजनाओं की उन्हें पर्याप्त जानकारी नही हैं। अध्ययन के अतंर्गत यह पाया गया कि जहाँ निम्न वर्ग की बालिकाओं में जहाँ उच्च शिक्षा की ललक पाई गई वही रोजगार के प्रति उनमें जागरूकता पाई गई। निम्न वर्ग की बालिकाओं कों शासन की उचित जानकारी का व्यापक प्रचार किया जाए तथा विभिन्न स्तरों मे ंव्यापक रूप में शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए।

02. चंद्राकार, रेखा (2005) – हरिजन कन्या छात्र – वृत्ति योजना का शिक्षा मे ं प्रभाव का अध्ययन पश्चात् पाया गया है, कि रायपुर जिले में हरिजन कन्या छात्रवृत्ति योजना का व्यापक प्रभाव देखा गया एवं इसमे हरिजन बालिकाओं में शिक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता देखी गई । अपितु उचित एवं पर्णू जानकारी के अभाव में यह तथ्य सामने आया कि कई बालिका इसका उचित उपयोग नहीं कर पाई। इसके लिए आवश्यक है कि इस योजना का व्यापक प्रचार – प्रसार करना जिससे कि इसका उपयोग उचित रूप से ही सके।

समस्या का कथन–

महाविद्यालय स्तर की बालिकाओं की शिक्षा कि समस्याओं के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन।

2.3 अध्ययन का उद्देश्य :–

महाविद्यालय स्तर कि बालिकाओं की शिक्षा कि समस्याओं के सबंध मे ं निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्माण किया गया है :–

- निम्न वर्ग व उच्च वर्ग परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- निम्न निम्न वर्ग व उच्च वर्ग परिवार की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।
- निम्न वर्ग व उच्च वर्ग परिवार की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना।
- निम्न वर्ग व उच्च वर्ग परिवार की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
- शिक्षा के माध्यम स`बालिकाओ ंकी जीवन स्तर के बारे में अध्ययन करना।

2.4 अध्ययन का परिसीमन :–

परिसीमा से तात्पर्य समस्या तथा अध्ययन के व्यापक क्षेत्र को सीमित करना है। शिक्षा तथा ज्ञान की सीमा अत्यंत विस्तृत है। किसी भी समस्या का व्यापक अध्ययन व्यापक या समग्र रूप से करना संभव नहीं है। क्योंकि इसमें समय और साधन अधिक लगते है। साथ ही व्यर्थ का अपव्यय अधिक होता है, अत: उपर्युक्त दोंषो से बचने के लिए समस्या के क्षेत्र को सीमित करना आवश्यक हो जाता है।

अतः शिक्षा के हेतु गुणोत्तर विकास को दृष्टिगत रखते हुए समय तथा साधनों को ध्यान में रखकर इस शोकर्त्ता द्वारा परिसीमाऐं निध ारित की गई।

- प्रस्तुत अध्यापन हेतु रायपुर जिले का चयन किया गया है।
- प्रस्तुत अध्यापन हेतु रायपुर जिले के अतंर्गत रायपुर रायपुर नगर का चयन किया गया है।
- प्रस्तुत अध्यापन हेतु रायपुर नगर के 5 महाविद्यालयों का चयन किया गया है।
- प्रस्तुत अध्यापन हेतु रायपुर नगर के पांच महाविद्यालय के अध्यनरत 100 बालिकाओं का परीक्षण किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन के अतंर्गत बी ए में अध्ययनरत्बालिकाओं की सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास और पारिवारिक विकास से संबंधित जानकारी ली गई है।
- प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा साद्वात्कार अनुसूची के निर्माण के लिए ने अपनें शोध निर्देशक से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन हेतु बी ए में अध्ययनरत् बालिकाओं तक सीमित है।
- अध्ययन में केवल महाविद्यालय के बालिका से ही भाग लेंगी जो बी.ए. की छात्रा है।
- प्रस्तुत अध्यापन हेतु रायपुर जिले का चयन किया गया है।
- प्रस्तुत अध्यापन हेतु रायपुर जिले के अतंर्गत रायपुर रायपुर नगर का चयन किया गया है।
- प्रस्तुत अध्यापन हेतु रायपुर नगर के 5 महाविद्यालयों का चयन किया गया है।
- प्रस्तुत अध्यापन हेतु रायपुर नगर के पांच महाविद्यालय के अध्यनरत 100 बालिकाओं का परीक्षण किया गया है।

स्वतंत्र चर – बालिका शिक्षा की समस्याएँ।

12. अपकरणों का चयन –

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए शोध निर्देशक की सहायता से स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है

13.सांख्यिकी विश्लेशण –

प्रस्तुत शोध अध्ययन परिकल्पना की पुष्टि एवं जांच हेतु सांख्यिकी विश्लेशण का उपयोग किया जाएगा इसके लिए काई वर्ग की गणना की जाएगी।

सांख्यिकी अभिप्रयोग :–

संबंधित शोध प्रबंध के लिए निम्न सांख्यिकीय सूत्री का प्रयोग कर गणना किया गया है।

सूत्र

$$x^2 = \frac{\sum(fo - fe)^2}{fe}$$

यहाँ

x^2 = काई वर्ग परिक्षण

Σ =योग

fo =प्रेक्षित आवृतियाँ

- परिकल्पना एच1 –

बालिकाओं की सामाजिक विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है–

IMPACT FACT - 8.1 | ISSN : 2582-919X

(सारणी क्रंमाक 4.1)
बालिकाओं की सामाजिक विकास से संबंधित विवरण

क .	कथन	हाँ की संख्या प्रतिशतमें	नहीं की संख्या प्रतिशतमें
1	क्याआपबालिकाओंकोशिक्षितकरने के पक्ष मेंहै।	100	0
2	क्याआपबालिकाओंकोउच्चशिक्षा के पक्ष में नही है।	95	5
3	क्याआपनौकरीपाने के पक्ष मेंहै?	90	10
4	क्याआपदहेजप्रथा के विरूद्ध है?	95	5
5	क्याआपबाल–विवाहकिपक्ष में है?	0	100

परिणाम :–

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण उत्तरदाताओं ने बालिका शिक्षा को महत्व देकर अपनी जानकारी हाँ में प्रदान की तथा 95 प्रतिशत पालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा के पक्ष में है एवं 5 प्रतिशत अभिभावक उच्च शिक्षा के पक्ष में नहीं है।

(संदर्भ तालिका क्रंमाक 4.1)
बालिकाओं की सामाजिक विकास से संबंधित विवरण

सुझाव

प्रस्तुत लघुशोध के अध्ययन से जो हमें ज्ञात हुआ उससे स्पष्ट है, कि बालिकाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है जिसमें सुधार करना बति आवश्यक है। पुरूष प्रधान देश होने के कारण बालिकाओं की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है।

बालिकाओं की दशा में सुधारने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिएः–

- बालिकाओं के जीवन को बेहतर बनाना।
- सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करना।
- बालिका शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक और राजलीतिक निहितार्थ का अध्ययन करना।
- बालिका शिक्षा को बेहतर बनानें के लिए सिफारिशें देना।
- बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारको का अध्ययन करना।

ग्रंथ – सूची

ग्रंथ सूची

1 पाण्डेय, राशकल (1887) –''शिक्षा दर्शन'', आगरा विनोद पुस्तक मंदिर, तेईसवसं सस्करण, पृष्ठ सख्या – 25–30

2 राम पारसनाथ एवं भटनगर, (1973) – ''अनुसधांन परिचय'', आगरा लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पृष्ठ सख्या – 62–90

***

IMPACT FACT - 8.1 | ISSN : 2582-919X

To Study the Impact of Emotional Intelligence on Academic Achievement of Middle School Students

Research Scholar : Anjali Lahre
M.Ed. Student
Affiliation: Pragati College,
Choubey Colony, Raipur (C.G.)
Contact : 9111393798, 7389511018
Address : H.N. 0456, Street No. 14,
Ekta Nagar, Near Electricity Pole,
Mana Camp, Raipur C.G., Pin 492015
Email : anjalilahre99@gmail.com

Research Guide:
Dr. Soumya Nayyar,
Principal & Professor,
Affiliation Pragati College,
Choubey colony, Raipur
(C.G.)

ABSTRACT

This study explores the role of emotional intelligence (EI) in shaping academic outcomes among

middle s school students in Raipur district. Drawing from a sample of 100 seventh-grade students from both government and private schools, the research uses a quantitative method to analyze the correlation between EI and academic performance. Emotional intelligence was assessed using the Multi-Factor Emotional Intelligence Scale (Shanuwal, 2002), while academic achievement was based on students' previous year results. Findings reveal that student with higher emotional intelligence demonstrate stronger academic performance. Moreover, girls a and private school students showed significantly higher EI and academic success compared to boys and government school students. The study emphasizes the importance of incorporating emotional skill development into educational practices to enhance holistic student success.

1.Introduction

Academic performance in schools has traditionally been evaluated based on intellectual and cognitive abilities. However, with increasing focus on holistic education, emotional intelligence has emerged as a key determinant of student success. Emotional intelligence—defined as the ¬ability to perceive, regulate, and manage emotions—affects students' motivation, interpersonal relationships, stress handling, and ultimately academic performance. Middle school years are formative in emotional development, making this stage crucial for studying the influence of EI. This paper aims to investigate the relationship between EI and academic achievement among Class 7 students from Raipur's government and private schools, with a focus on gender differences. This study is grounded in Goleman's and Bar-On's theories of EI, which propose that emotional and social skills are just as important as cognitive abilities for academic and life success.

2.Objectives and Hypotheses

Objectives:

To compare impact of Emotional Intelligence on academic achievement between boys and girls.

To compare impact of Emotional Intelligence on academic achievement between students of government and private schools.

Hypotheses:

H1: There is no significant difference between Emotional Intelligence and academic achievement of boys and girls.

H2: There is no significant difference between emotional intelligence and academic achievement of boys of class 7th students of government and private school.

3.Methodology

This descriptive survey research used stratified random sampling to select 100 Class 7 students—50 boys and 50 girls—from three private and two government schools in Raipur.

Tools Used:

Multi-Factor Emotional Intelligence Scale (Shanuwal, 2002) Academic achievement based on Class 6 annual results.

Data Collection:

Surveys were conducted in school settings under supervision. Students responded to ques-

tions measuring emotional perception, understanding, regulation, and application. Academic scores were collected from school records.

Statistical Techniques:

Mean, standard deviation, and t-tests were used to analyze group differences and test hypotheses.

4.Results

Gender	Frequency n	Mean	S. D	Critical value of t		t	Remarks
				0.05	0.01		
Boys	50	30.6	9.37	±1.984	±2.626	3.66	Significant
Girls	50	40.3	13.25				

DF=53

Result-

It is clear that from the above table 4.3thefrequency of the boys and girls are 50 of government and private school, and the mean valuesare30.6forboysand40.3forgirls, the standard deviation is 9.37 and 13.25 respectively. There is a significant difference between in the mean values of Boys and girls school students. Here, the t test value at 53 degrees of freedom at 0.05 level of significance. Calculated value of t test is -3.66. Hence there is a significant difference in the government and private boys and girls , thushypothesis rejected.

Graph 4.1

Performance score of Government and Private School boys and Girls Students

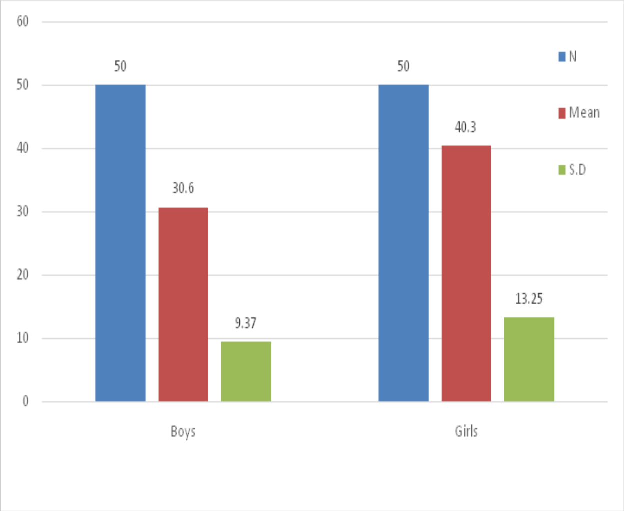

Type of school	Frequency n	Mean	S. D	Critical value of t		t	Remarks
				0.05	0.01		
Government	25	38.4	9.27	±2.04	±2.75	0.82	Insignificant
Private	25	36	8.78				

Df= 31

Result-

It is clear from the above table 4.1that the frequency of the students for the score of Emotionalintelligence amongboysofgovernmentis50andprivate is50.Andthemean value is38.4and36respectively,thestandarddeviation is 9.27and8.78respectively.

Here, the t test value at 31 degrees of freedom at 0.05 level of significance. Calculated value of t test is 0.82.

Hence there is no significant difference between emotional intelligence and academic achievementsof boys of class 7th of government and private school. Thus, the hypothesis is accepted.

Graph No. 4.2

Graph representing frequency, mean score, standard deviation among boys of class 7th

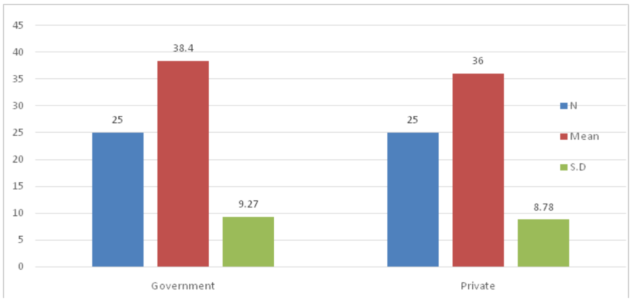

5.Discussion and Conclusion

The study underscores the critical role emotional intelligence plays in educational

achievement. Emotional competencies such as empathy, emotional regulation, and

motivation is linked with better academic performance. Gender differences indicate that girls tend to be more emotionally intelligent, which contributes to their success. The superior performance of private school students suggests envi-

IMPACT FACT - 8.1 | ISSN : 2582-919X

ronmental and institutional influences on emotional development.

Conclusion:

Emotional intelligence is not merely an accessory skill but a foundational one that impacts students' academic journeys. The study advocates for the integration of social-emotional learning (SEL) programs within school curricula. Teachers should receive training to foster emotionally rich learning environments. In doing so, schools can better prepare students not just for exams but for life.

6.Recommendations

- Incorporate emotional learning and mindfulness activities in the curriculum.
- Conduct regular emotional check-ins and reflection sessions.
- Implement SEL programs across government and private institutions.
- Train educators in emotional skill development and classroom empathy.

7.Limitations and Further Study

- The study was limited to Class 7 students in Raipur district.
- Future research should consider larger and more diverse populations.
- Longitudinal studies could explore how EI impacts long-term academic and career outcomes.
- Comparative studies across different states and socio-economic backgrounds could yield deeper insights.

8.Bibliography

- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
- Bar-On, R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-i). Multi-Health Systems.
- Chamundeswari, S. (2013). Emotional intelligence and academic achievement among students. International Journal of Academic Research.
- Asmari, A. R. A. (2014). Emotional Intelligence and Academic Achievement: A Gender- Based Study. Journal of Education and Practice.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.jstor.org
https://www.scienced irect.com
https://link.springer.com
https://www.academia.edu
https://www.tand fonline.com
https://www.semanticscholar.org
https://www.researchgate.net
https://www.jetir.org

***

“कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियो के शैक्षिक चिंता का तुलनात्मक अध्ययन”

शोधकर्ता- सुमन वर्मा
एम.एड. (प्रशिक्षार्थी),
प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
पता - वार्ड नं.18, डॉ. खूबचंद बघेल चौक शिक्षक कॉलोनी तिल्दा नेवरा, (छ.ग.) 493114
सम्पर्क : 8103139098
ई -मेंल - gunjansharma0712@gmail.com

निर्देशिका- सुमन वर्मा
सहायक प्रध्यापक,
प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
सम्पर्क : 9907718875
ई -मेंल - gunjansharma0712@gmail.com

सारांश

यह अध्ययन रायपुर ज़िले में स्थित ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के नवमीं कक्षा के पर केंद्रित था। अध्ययन का उद्देश्य था कि विद्यार्थीयों में होने वाले शैक्षित चिंता का अध्ययन करना था। शोध में कुल 100 विद्यार्थीयों को सामिल किया गया था।

प्रस्तावना

शिक्षा मानवीय चेतना का वह ज्योतिर्मय सुसंस्कृत पक्ष है जिससे उसके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास होता है। शिक्षा के द्वारा मानव का मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक व आर्थिक विकास होता है। अन्नंत काल से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता आया है और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज मानव सभ्यता के ऊँचे शिखर पर चढ़ने में समर्थ हुआ है। प्राचीन समय में विभिन्न देशों में समाज के आदशों और उद्देश्यों के अनुसार ‘शिक्षा‘ को विभिन्न अर्थ दिए गए थे।

उदाहरणनार्थः-

प्राचीन भारत में शिक्षा को आत्मज्ञान और आत्म प्रकाशन का साधन माना गया था। आज शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान का माध्यम ही नहीं है अपितु रोजगार का जरिया भी बन गया है। पहले की अपेक्षा आज शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विशेष, प्रविधि एवं अनुशासन की आवश्यकता होती है आज बच्चे को शिक्षा के माध्यम से न केवल भौतिक बातों का ज्ञान, अपितु अन्य कई व्यवहारिक पक्षों से जुड़े ज्ञान विषयक पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है, ताकि वे न केवल आयोजित करे बल्कि भविष्य में अपनी जीविका हेतु सार्थक विकल्पों का चयन कर सका

शैक्षिक चिंता

चिंता वह भावना है जिससे व्यक्ति अपने आपको अकेला और असहाय समझता है। व्यक्ति उस भावना की उपस्थिति भी सामाजिक वातावरण को शत्रुतापूर्ण व बिरोधी ही नहीं मानता है बल्कि वह सामाजिक वातावरण में भय भी रखता है। चिंता की भावना उस समय भी उत्पन्न हो सकती है जब व्यक्ति की सुरक्षा भावना को चोट पहुंचती है।

चिंता विकारों के एक ऐसा समुह है जो मानसिक विकार चिंता और डर की भावनाएँ उत्पन्न होती है। विद्यार्थी की शैक्षिक चिंता को हम जीवन के प्रति बाणात्मक अभिवृति के रूप में देख सकते हैं। आज के इस सुरक्षित एवं बहुप्रतिस्पधी बातावरण में व्यक्ति को जब अपेक्षित सफलताएं नहीं मिलती तो उसे अपने भविष्य की सुरक्षा की भावना से चोट लगती है। और वह सामान्य व्यक्ति से अधिक चिंताग्रस्त हो जाता है। तथा लगातार ऐसी परिस्थिति में रहने के कारण उसकी अभिवृति जीवन के विपरीत या ऋणात्मक होने लगती है।

समस्या का कथन

“ कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक चिंता का तुलनात्मक अध्ययन ”

प्रकार्यात्मक परिभाषा

चिंता से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, चाहे वह एक छोटा बालक हो या वृद्ध व्यक्ति बालक को अपने परीक्षा चिंता, पाठ्यक्रम की चिंता, संस्कृत विषय की उच्चारण सम्बन्धि चिता होती है तो बुवाओ को उज्वल भविष्य की कभी-कभी इस प्रकार की चिंता से व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार भी हो जाता है।

राजर्स के अनुसारः- चिंता एक ऐसी अनुभुति है जो उनकी स्वयं की विचारधारा में भाग उत्पन्न करती है।‘

आर-एम- के अनुसार (1/4 1950 1/2) भय के संकेत की अनुभुति की कोई माता जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता है चिंता कहलाती है।

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी शैक्षिक शोध का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक समस्याओं का समाधान एवं उस समस्या के समाधान द्वारा शिक्षा का विस्तार कर ज्ञान भण्डार में वृद्धि करना होता है। कोई भी समस्या उद्देश्य पूर्ति में आई बाधा के कारण उत्पन्न होती है।अध्ययन के उद्देश्यों के निर्धारण से पहले शिक्षा के उद्देश्य को जानेगें- जैसा कि महात्मा गाँधी जी ने कहा है- ‘शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा में अन्तर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। वही सच्ची शिक्षा है जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है।

उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को प्रेरित करना भी है। अतएव यह आवश्यक है कि बालक के विकास के लिए उसकी परेशानियों को समझना तथा उसे शिक्षा द्वारा संभवतः दूर करने का प्रयास करना ।

प्रस्तुत लघुशोध के अध्ययन में निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं-
(1) ग्रामीण विद्यार्थी की शिक्षा चिंता का अध्ययन करना,
(2) गहरी छात्र-छात्राओं की शैक्षिक चिंता का अध्ययन ।
(3) ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक चिंता का तुलनात्मक अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पना

परिकल्पना से तात्पर्य उस संभावित उत्तर से होता है, जो समस्या

समाधान के लिए हम सोचते है। यह समस्या समाधान के लिए उचित दिशा प्रदान करती है जिस पर चलकर हम समस्या का समाधान सही रूप में निकाल पाते हैं। अतः परिकल्पना को संभावित समाधान या सिद्धांत भी कहा जाता है। जिसे अस्थायी रूप से सही मानकर उसकी पुष्टि करने का प्रयास किया जाता है।

परिकल्पना की विशेषताएँ-

1. परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए क्योंकि वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक ज्ञान की रचना संभव होती है ।
2. परिकल्पना प्राकृतिक नियमों जो सत्य प्रमाणित किए जा चुके है, उनके विरोध में नहीं होती है ।
3.परिकल्पना संभवतः अपने अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित अन्य परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए ।
4. परिकल्पना में तर्क संगत एकता तथा बोधगम्यता, सरलतम रूप से स्पष्ट होनी चाहिए ।
5. परिकल्पना से अनेक परिणाम उपलब्ध होने चाहिए अतः परिकल्पना निगमन चिंतन पर आधारित होना चाहिए ।

साख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध हेतु निर्मित की गई परिकल्पाओं की पुष्टि करना अनुसंधान का मूल उद्देश्य है जिसके लिये प्रदत्तों की व्याख्या विश्लेषण के आधार पर सांख्यिकीय का उपयोग किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय प्रविधियों प्रयोग में लाई गई है:

1. केन्द्रीय प्रवृत्ति माप-माध्य (Mean)
2. प्रमाप विचलन-मानक विचलन (Standard Deviation)
3. सार्थक अन्तर के लिये क्रान्तिक अनुपात (Critical Ratio)
4. 1-Test

परिकल्पना का प्रमापीकरण एवं परिणाम

सारणी क्रमांक 1

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांकों का माध्य प्रमाप विचलन, C. R. मूल्य तथा सार्थकता दर्शाने वाली सारणी

क्र.	चर	संख्या	माध्य	मानकविचलन	C. R	सार्थकहै
1	ग्रामीणविद्यार्थी	100	10.63	3.26	2.08	0.05 सार्थकहै
2	शहरीविद्यार्थी	100	11.63	3.34		

df = 198

व्याख्या :-

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि 100 ग्रामीण एवं 100 शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको का माध्य क्रमशः 10.63 व 11.63 तथा उनका प्रभाव विचलन 3.26 व 3.34 है। ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्य में अंतर है, ग्रामीण विद्यार्थियों में शैक्षिक चिंता शहरी विद्यार्थियों से कम है।

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्य में अन्तर की सार्थकता के लिए C.R. मूल्य की गणना की गई जो 2.08 प्राप्त हुआ। 198 df के लिए 05 स्तर पर 1 का टेबल मूल्य 1.96 है, जो C.R. की गणना मूल्य से कम है। अतः ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्यों में सार्थक अंतर पाया गया। अतः परिकल्पना ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं विद्यार्थियों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा अतः अस्वीकृत हुई ।

आरेख क्रमांक 1

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांकों की संख्या, माध्य एवं प्रमाप विचलन दर्शाने वाला आरेख

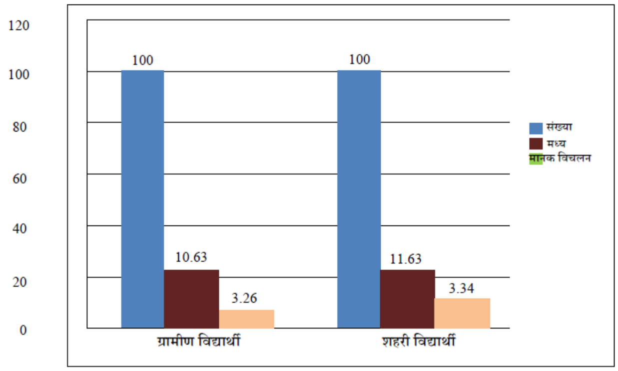

परिकल्पना क्रमांक H2 –

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं के बालकों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक 2

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं के बालकों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको का माध्य प्रमाप विचलन C.R. मूल्य तथा सार्थकता दर्शाने वाली सारणी

क्र.	चर	संख्या	माध्य	मानक विचलन	C. R	सार्थक है
1	ग्रामीण विद्यार्थी	50	10.94	2.86	1.97	0.05 सार्थक है
2	शहरी विद्यार्थी	50	10.88	4.38		

df = 98

व्याख्या :-

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि 50 ग्रामीण व 50 शहरी विद्यालय में अध्ययनरत् बालको में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्य क्रमशः 10.94 व 10.88 है तथा मानक विचलन 2.86 व 4.38 है। ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् बालकों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्य में अंतर पाया गया। ग्रामीण एवं शहरी बालको में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्य में अंतर की सार्थकता के लिए C.R. मूल्य की गणना की गई जो 1.97 आया है। 98 df के लिए 05 स्तर पर ज टेबल मूल्य 1.96 जो कि गणना मूल्य से कम है। इस प्रकार परिकल्पना ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9वीं के बालको में शैक्षिक चिंता के प्राप्ताकों के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा । अतः परिकल्पना अस्वीकृत हुई।

आरेख क्रमांक 2

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 वीं के बालकों में

शैक्षिक चिंता के प्राप्तांकों की संख्या, माध्य एवं प्रमाप विचलन दर्शाने वाला आरेख

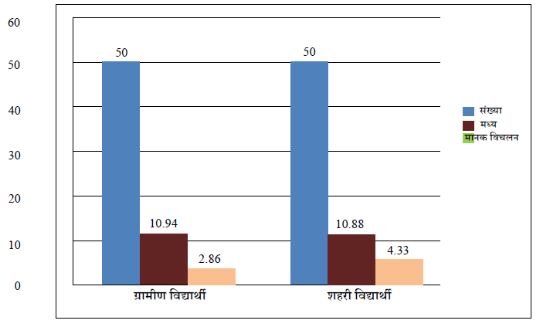

परिकल्पना क्रमांक H3 -

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं के बालिकाओं में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा ।

सारणी क्रमांक 3

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं के बालिकाओं में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको का माध्य प्रमाप विचलन C. R. मूल्य तथा सार्थकता दर्शाने वाली

सारणी

क्र.	चर	संख्या	माध्य	मानक विचलन	C. R	सार्थक है
1	ग्रामीण विद्यार्थी	50	12.32	3.64	2.82	0.05
2	शहरी विद्यार्थी	50	10.38	3.39		सार्थक है

df = 98

व्याख्या :- उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि 50 ग्रामीण व 50 शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिका में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्य क्रमशः 12.32 व 10.38 तथा मानक विचलन 3.64 व 3.34 है। ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं में शैक्षिक चिंता के माध्य में अंतर पाया गया। ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांको के माध्य में अंतर की सार्थकता के लिए C.R. मूल्य की गणना की गई जो 2.82 आया है। 98 df के लिए 05 स्तर पर 1 का टेबल मुख्य 0.01 जो कि गणना मूल्य से कम है। अतः ग्रामीण एवं शहरी कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं के बालिकाओं में प्राप्तांको की माध्य में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा। अतः परिकल्पना अस्वीकृत हुई ।

आरेख क्रमांक 3

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं के बालकों में शैक्षिक चिंता के प्राप्तांकों की संख्या, माध्य एवं प्रमाप विचलन दर्शाने वाला आरेख

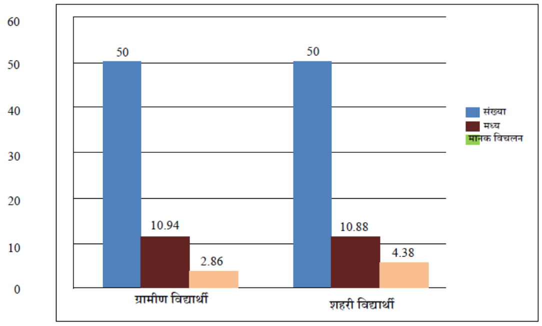

निष्कर्ष:-

परिकल्पना के परिणाम से स्पष्ट होता है, कि ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक चिंता में अंतर पाया गया इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि वर्तमान समय में शहरी विद्यार्थी शिक्षा के प्रति जितने जागरूक हैं ग्रामीण विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उतना जागरूक नहीं हैं। अतः शहरी अभिभावकों की अपेक्षा ग्रामीण अभिभावक भी शिक्षा को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। जिसके कारण दोनों विद्यार्थियों के शैक्षिक चिंता में अंतर परिलक्षित होता है।

सुझाव

1. प्रस्तुत लघुशोध में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक चिंता के संदर्भ में निम्न लिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए है-
2. माता-पिता को बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु हर संभव प्रयास कर तथा अपेक्षा रखें जिससे बालक चिंता ग्रस्त न हो ।
3. शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा बालक के मन में शिक्षा को लेकर किसी प्रकार का नकारात्मक विचार न आने देने का प्रयास करना चाहिए ।
4. विद्यार्थियों के मानसिक विकास हेतु उन्हें अध्ययनरत् एवं अन्य स्वरूप गतिविधि हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जिससे विद्यार्थियों को उस प्रकार की वातावरण का सामना करना पड़े जो शैक्षिक चिंता को दूर कर पायें ।
5. शिक्षकों को विद्यार्थियों को उत्सावर्धन करना चाहिए ।
6. शिक्षकों को उनके भविष्य के बारे में अवगत करना चाहिए एवं निर्भीक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

▪ डेविड एम. हैमिल्टन होली (2012 निहित नस्लीय मूल्यांकन और रूढ़िवद्धता चिंता प्रभाव

▪ माधुर एस. खान डबल्यू (अक्टूबर 2011 परीक्षा चिंता और स्कूली बच्चों के बीच शैक्षिक प्रदर्शन पर सम्मोहन का प्रभाव

▪ सुसान (2011 अस्तित्व की चिंता और तथा कथित न्यूरोटिक चिंता के बीच अंतर क्या है सच्चे जीवन शक्ति की अनिवार्य शर्त

▪ हुआग (2010) 'चिंता और प्रतिक्रिया नकारात्मक'

▪ देबिनगेराब्द (2008 असामान्य मनोविज्ञान टोरंटो वेशेनिका'

▪ डाउनी जोनाथन (2008 प्रीमियम विकल्प चिंता टाइम्स लंदन को प्राप्त किया गया'

▪ गोल्डा एस. (2007 विता विकारो की रोकथाम मनोरोग 19 (6)' के इंटरनेशनल की समीक्षा'

▪ पारस नाथ राय (2002) 'अनुसंधान परिचय आगरा लक्ष्मीनारायण अग्रवाल'

▪ बारलो डेविड एच (2000) 'भावना सिद्धांत के नजरिए से चिंता से रहस्यों और उसके विकारों'

▪ पाठक पी.डी. (2000) 'शिक्षा मनोविज्ञान आगरा विनोद पुस्तक मंदिर'

What Reels May Come

Sleep, fingers, brain. Or maybe brain, fingers, sleep. Or the random order that I chose. Anyone one of those can be fatal. Lethal. Deadly

● **Ranjona Banerjee** | The writer is a senior journalist who writes on media affairs, politics and social trends.

As anyone who "scrolls" knows however, there are reels for everything. Including how to stop scrolling, how to get your fingers back, how to blow smoke up your..., how to regrow your brain, how to sleep, how not to sleep, how to eat, what not to eat, what to wear, what not to wear. What to wear when you're 30, 70, 370. All of it. — Internet

I cannot tell a lie and pretend to be superior. I do watch reels on that social media site. Obviously not the banned one: Gosh no, I would never do that. I don't even have a subscription to one of those virtual private... shh. But the other one owned by some evil tech billionaire or the other, the one which allows little clips from the banned site, I watch that. Every night before I sleep, I have to get my little dopamine fix. I now realise that every do-gooder well-wisher will tell me how bad this is for me. My fingers will fall off, my brain will decompose and I'll destroy my whole sleeping pattern. I've put those in no particular order because I'm not sure which is the worst. Although am sure someone will have a perfectly concocted theory on that as well.

I am rooting for, in order of importance: Sleep, fingers, brain. Or maybe brain, fingers, sleep. Or the random order that I chose. Anyone one of those can be fatal. Lethal. Deadly.

As anyone who "scrolls" knows however, there are reels for everything. Including how to stop scrolling, how to get your fingers back, how to blow smoke up your..., how to regrow your brain, how to sleep, how not to sleep, how

to eat, what not to eat, what to wear, what not to wear. What to wear when you're 30, 70, 370. All of it.

How to exercise, how not to exercise. Who to believe. Who not to believe. What celebs look like. What they should look like. What you should look like. Who's trying to enter your life through our phone. How to save yourself. What suitcase to take to a foreign country. Don't laugh. This is big. Very important. I have even noticed a link to what I suspect is a whole article on what baggage to carry on holiday, probably inspired by the popularity of these little 30-second recordings.

And then, since you're travelling: Where to go, how to go where you want to go, what to eat, how to eat what you want to eat, on and on and on. Then there's the backlash tourist reel: How to expect to be treated in my country, that country, some other country if you are a pesky unwelcome tourist.

Sometimes I find myself particularly drawn to videos of babies and infants being cute. This you can blame on my age. Long-nailed overly made-up little women tapping things to buy, which they've got for free, or using some expression-less — and yet at the same time breathless — voice to tell you how to make some horrible-looking healthy meal, these do not appeal.

You know what I mean — "influencers". But then I wonder about the future of these little children, who do not know they are being made famous. And eventually, as you

"How to exercise, how not to exercise. Who to believe. Who not to believe. What celebs look like. What they should look like. What you should look like. Who's trying to enter your life through our phone. How to save yourself. What suitcase to take to a foreign country. Don't laugh. This is big. Very important. I have even noticed a link to what I suspect is a whole article on what baggage to carry on holiday, probably inspired by the popularity of these little 30-second recordings.
Sometimes I find myself particularly drawn to videos of babies and infants being cute. This you can blame on my age. Long-nailed overly made-up little women tapping things to buy, which they've got for free, or using some expression-less — and yet at the same time breathless — voice to tell you how to make some horrible-looking healthy meal, these do not appeal.

watch them, they start endorsing products. Which means another form of exploitation by greedy parents. And the massive commercial machine has managed to gobble everything in its path.

I fear the damage done will be far worse than whatever happens to my fingers. Because the collective brain of humanity is being fogged. And by us, willingly if unwittingly.

And instructed, permanently instructed. Don't say this, do that, feel the other thing. The problem is that the directions contradict each other depending on who's issuing them. Wellness-conscious and health-filled people want us to be happy; regressive people want us to listen to them because they know how we should feel, aware people want us to listen to them because they know how we ought to feel. And free will people want to be how they want to be. Contrarian annoyances, clearly.

There's a coffee shop somewhere which won't let you in unless you're smiling. I hear the "positivity at any cost" brigade cheering. So wonderful. A smile is what this terrible world needs. So sweet and affirming, 'gratituding' and whatever else is the trendy word right now. So what if this constant need to be happy can have a deleterious effect on what you're actually feeling? The loss of a loved one for instance does not really lead to happiness in many people. But they may still want a cup of coffee.

Do they deserve it, if they cannot paste a meaningless mouth-stretch on their sad faces on demand? One of the bitter lessons of growing older is discovering that freedom gets increasingly restricted just when you thought it was heading your way. The reels are full of generational conflict, usually funny. Though I guess humour depends on which side of the camera you're on. From where I'm sitting, age makes things a lot funnier than they might seem to younger people. Can you see my smug smile? Good.

I meant you too, as you wallow in your age-appropriate confusion. It is how it is. However, to get back to where I started. There are some advantages to these reels. In order; music, science, history, art, political activism and comedy. Not all of these help you to sleep easy. And those pesky algorithms are ready to take you down any number of rabbit holes.

So you learn to avoid the important "advice" about some green healthy "natural" gunk you have to eat, put on your face, apply to your walls or whatever the latest craze is. Don't take offence at the colour I chose, even though I respect your right to be permanently offended especially if you're a well-meaning younger person full of the milk of human sentimentality and sanctimonious.

I respect that right as well. It's just that I could well have written yellow, orange, heliotrope. Please don't worry too much about me. You may have gathered that I'm not a very sweet type of a person. Instead of offering any gratuitous advice which I will not take, you could just take bets on which finger will fall off first, how much wrist surgery will cost me and how soon my brain will atrophy. And most importantly, will I ever be able to fall asleep at whatever is the correct time these days to fall asleep. Do let me know. Or rather, don't.

Ranjona Banerji is a senior Indian journalist and commentator with over four decades of experience in the field. She is known for her insightful commentary on politics, media, and social trends.